कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष 61 अंक 10 मुंबई सितम्बर 2017

राष्ट्रपति भवन में विश्व 'मधुमक्खी दिवस' मनाया गया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 61 अंक 10 मुंबई सितम्बर 2017

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
बी.एच. अनिल कुमार

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एव
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से
खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 38

आयोग ने राष्ट्रपति भवन से 'मधु क्रांति' की शुरुआत कर 'विश्व मधुमक्खी दिवस' मनाया ...
मुंबई में 'विश्व मधुमक्खी दिवस' ...
पूरे देश में आयोग द्वारा 'विश्व मधुमक्खी दिवस' मनाया गया ...
खादी हुई वैश्विक, अमेरिकी राजदूत ने स्वतंत्रता दिवस पर पहनी खादी साड़ी ...
आयोग ने ऐतिहासिक शहर पुणे में इतिहास बनाया ...
खादी इंडिया फ्रेंचाइजी का तिरुवल्ला में उद्घाटन ...
आयोग के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के कामकाज की समीक्षा ...
आयोग ने पम्पोर, जम्मू और कश्मीर में ऐतिहासिक प्रशिक्षण स्थल को पुनर्जीवित किया ...
कालीकट में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता अभियान-सह-लोक शिक्षा कार्यक्रम ...
आयोग मुख्यालय में मनाया गया 71 वां स्वतंत्रता दिवस ...
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नर्मदा घाटी में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू किया ...
आयोग की वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में आंचलिक समीक्षा बैठक संपन्न ...
सशस्त्र बल जल्द ही खादी वर्दी पहनेंगे ...
फैशन के बीच खादी की हिट, जल्द ही पेरिस, दुबई में स्टोर ...
अखिल भारतीय केवीआईसी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा ...
आयोग की 647वीं बैठक का कार्यवृत ...

लेख ....

सोलर चरखा प्रोजेक्ट - ग्राम खनवाँ, जिला नवादा
-गिरिराज सिंह

सरलता ही हिंदी को आगे ले जाएगी
-विजय गोयल

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ............39 से 41

विश्व 'मधुमक्खी दिवस'

आयोग ने राष्ट्रपति भवन से 'मधु क्रांति' की शुरुआत कर विश्व 'मधुमक्खी दिवस' मनाया

नयी दिल्ली, 19 अगस्त, 2017: खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आज राष्ट्रपति भवन से मधु मिशन की शुरूआत की। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने पिछले माह राष्ट्रपति भवन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित मधुमक्खी वाटिका का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति द्वारा मधुमक्खी वाटिका के दौरे का उद्देश्य "विश्व मधु मक्खी दिवस" मनाना है।

राष्ट्र को बदलने के लिए, हमेशा नए विचारों की तलाश में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि "श्वेतक्रांति" के साथ "स्वीट क्रांति" भी शुरू करने की जरुरत है। प्रधान मंत्री का विजन भारत को शहद और मधुमक्खी मोम के उत्पादन में एक विश्व नेता बनाना

और परागण के जरिए फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को जानकारी देना है।

माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने न सिर्फ शहद उत्पादन की प्रक्रिया को समझने के लिए मधुवाटिका में अपना बहुमूल्य समय व्यतीत किया, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद विद्यालय के छात्रों को शहद की बोटल्स भी वितरित की। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के.सक्सेना ने उन्हें मधुवाटिका की स्थापना एवं उसके उद्देश्य के बारे में सविस्तार समझाया।

इस अवसर पर सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

श्री कलराज मिश्र, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपति भवन में 150 मधुमक्खी बक्से स्थापित किए हैं और अगले कुछ महीनों में 500 मधुमक्खी बक्से तक वृद्धि की जाएगी, जिससे राष्ट्रपति भवन में लगभग 15,000 कि.ग्राम उच्च गुणवत्तायुक्त शहद का उत्पादन होगा।

विश्व मधु मक्खी दिवस मनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सम्पूर्ण देश में स्कूली बच्चों को मधु की 10,000 बोटल्स वितरित करने का निर्णय लिया। जिसमें से प्रेसिडेंट ईस्ट के विशेष बच्चों को 250

बोटल्स, प्रेसिडेंट ईस्ट के डॉ.राजेंद्र प्रसाद विद्यालय के बच्चों को 1200 बोटल्स और इसके अलावा एन.डी.एम सी. के एन.पी. सहशिक्षण माध्यमिक स्कूल में 1200 बोटल्स वितरित की गई हैं।

स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए सांसद, लोकसभा श्रीमती मिनाक्षी लेखी ने शहद और शहद के महत्व पर ज़ोर डाला। उन्होंने कहा, शहद के पोषण मूल्य और इसके प्रभाव से "स्वस्थ भारत" के निर्माण में मधुमक्खी का हमारे जीवन में बहुत महत्त्व है, इसके लिए उन्होंने मधुमक्खियों के सामूहिक अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण दिया।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

के सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा, एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संयुक्त सचिव / खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.एच. अनिल कुमार उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने इस अवसर परकहा कि "हम माननीय प्रधान मंत्री के उद्देश्य, 'प्रत्येक परिवार को उनके दैनिक उपभोग के लिए अमूल्य अमृत मधु उपलब्ध कराने' के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं।" चूंकि शहद, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और रक्त शुद्ध करने में सहायक होता है, इसलिये हम स्कूलों में विधार्थियों के

बेहतर स्वास्थ्य के लिए शहद का वितरण कर रहे हैं।

मुंबई में विश्व मधुमक्खी दिवस

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मधु क्रांति के सपने को साकार करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय ने मुंबई स्थित विद्यालय विकास मंडल के श्रमिक विद्यालय, मेघवाडी, जोगेश्वरी, पूर्व के 1000 छात्रों के बीच 10 ग्राम शहद की बोतलें बांटकर मुंबई में विश्व मधु दिवस मनाया।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी आधिकारी, श्री वाई.के. बारामतीकर ने कहा, 'मधु क्रांति' केवल बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को ही बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन अगर वे मधुमक्खी पालन के कौशल को सीखते हैं तो उन्हें अपनी कमाई में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। मधुमक्खी पालन, कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने में भी मदद करता है, इस प्रकार उन्हें आत्महत्या करने से रोकता है।

श्रीमती स्मिता चौहान, स्कूल की ट्रस्टी ने इस व्यापक उद्देश्य हेतु अपने स्कूल का चयन करने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और अपने स्कूल परिसर में मधुमक्खी पालन की स्थापना की इच्छा व्यक्त की।

इस मौके पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी आधिकारी श्री एम. टी. वाकोडे ने मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया और इसके अद्भुत फायदे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि, वे मधुमक्खी पालन के माध्यम से 'सीखे भी और कमाएं' भी'।

आयोग के निदेशक, वित्त श्री बाबुल मंडल ने इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में और इसके वास्तविक उद्देश्य के बारे में संक्षेप में जानकारी दी।

अहमदाबाद में

विश्व मधुमक्खी दिवस के सुअवसर पर आयोग के राज्य कार्यालय, गुजरात की टीम ने विनय मंदिर स्कूल में विश्व शहद दिवस मनाया । जहाँ, आयोग के प्रतिनिधियों ने गांधी आश्रम, अहमदाबाद और शहद के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा लगभग 350 गर्ल्स छात्रों को शहद के सैंपल वितरित किये गए।

चंडीगढ़ में

विश्व मधुमक्खी दिवस, 19 अगस्त, 2017 को आयोग के राज्य कार्यालय, चंडीगढ़ में भी मनाया गया। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, मानव जाति के लिए मधुमक्खियों के महत्व और अवशिक्षण पर एक संगोष्ठी का आयोजन राज्य कार्यालय में किया गया, जिसमें पंजाब के मधुमक्खीपालकों, छात्रों, बिग-बी एसोसिएशन, शहद हट के निदेशक, केवीआईसी और केवीआईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। छात्रों के बीच 10 ग्राम शहद की बोटल वितरित भी की गई। इस उद्यम से सम्बंधित मधुमक्खीपालकों ने मधुमक्खी पालन पर अपने व्यक्तिगत विकास के अनुभव साझा किए।

वांये से दांयें अधिकारी- पीकेवीआईबी के संयुक्त निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब सरकार, पीकेवीआईबी के अधिकारी, केवीआईसी, चंडीगढ़ के उप निदेशक श्री वी.के.शर्मा, निदेशक, आरईजीडी, गैर सरकारी संगठन और बिग बी एसोसिएशन के अध्यक्ष-मंच पर दिखाई दे रहे हैं ।

विश्व के मधुमक्खी दिवस, 19 अगस्त 2017 को राज्य कार्यालय, अंबाला में मनाया गया। इस अवसर पर श्री वी. के. नागर, राज्य निदेशक, अंबाला ने मधुमक्खियों के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में डॉ. वेद प्रकाश, नेचर केयर सेंटर, अम्बाला कैंट, केवीआईसी और केवीआईबी के कर्मचारियों एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एसबीईसी, त्रिचुर, केरल में विश्व 'मधुमक्खी दिवस' समारोह

आयोग के त्रिचुर, केरल स्थित राज्य मधुमक्खीपालन विस्तार केंद्र ने अपने पास के स्कूलों के छात्रों को आमंत्रित कर मधुमक्खीपालन के महत्त्व की जानकारी देकर मधुमक्खी दिवस मनाया।

प्राकृतिक शहद
50 ग्राम
बच्चों को मुफ्त वितरण
Khadi India
द्वारा
विश्व 'मधुमक्खी दिवस'
19 अगस्त, 2017
सी.बी.आर.टी.आई., केवीआईसी, पुणे द्वारा पैकेजिंग

पूरे देश में आयोग द्वारा विश्व 'मधुमक्खी दिवस' मनाया गया

राष्ट्रपति भवन

अगरतला

अहमदाबाद

अम्बाला

देहरादून

गुवाहाटी

जम्मू एवं कश्मीर

एम.डी.टी.सी., बंगलुरू

खादी हुई वैश्विक, अमेरिकी राजदूत ने स्वतंत्रता दिवस पर पहनी खादी साड़ी

नई दिल्लीः स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा एक अस्त्र के रूप में उपयोग में लाए गये स्वदेशी वस्त्र 'खादी' गौरव का प्रतीक है - भारत में कार्यरत अमेरिकी राजदूत मैरी केलोस कार्लसन ने कनॉट प्लेस स्थित आयोग के 'खादी इंडिया' बिक्री केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान खादी साड़ी पहनने का निर्णय लिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की पत्नी संगीता सक्सेना से सुश्री कार्लसन ने खादी भवन में मुलाकात की, इस अवसर पर उन्होंने खादी के महत्व का वर्णन करने के अलावा अमेरिकी राजदूत को भारतीय पोशाक का चयन करने में भी मार्गदर्शन किया।

'खादी इंडिया' बिक्री केंद्र पर घंटे भर रहने के दौरान, सुश्री कार्लसन ने खादी उत्पादों की बड़ी रेंज को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने तीन दर्जन से अधिक साड़ी को छांटकर अंत में अपने लिए पांच सबसे अच्छी साड़ियों का चयन किया, जो रॉ-सिल्क, मटका रेशम और कटिया सिल्क खादी वस्त्र में से थी, इस अवसर पर उन्होंने मिरर वर्क के भी खादी वस्त्र देखे। इतना ही नहीं उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 'खादी इंडिया' आउटलेट की अपनी वीडियो भी साझा की। इससे पूर्व, उन्होंने महात्मा गांधी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की।

इस बीच, अमेरिकी राजदूत का 'खादी इंडिया' आउटलेट में दौरा करने पर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह खादी कारीगरों के लिए एक सम्मान है और "हमारे लिए यह बेहतर गौरव का क्षण है कि विश्व के पहले लोकतंत्र के राजदूत ने स्वंतत्रता दिवस के 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर साड़ी का चयन करने के लिए हमारे आउटलेट का दौरा किया है।"

24 और 25 अगस्त 2017 को अहमदाबाद में आयोजित विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की बैठक का एक दृश्य। बैठक में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.एच. अनिलकुमार, आईएएस ने समिति के माननीय अध्यक्ष श्री नरेन्द्र बडानीया और अन्य सभी माननीय सदस्य का स्वागत किया।

डीआरपीएससी समिति के गुजरात दौरे के दौरान 24-25 अगस्त 2017 को राज्य कार्यालय, गुजरात द्वारा बैठक स्थल पर एक लघु प्रदर्शनी आयोजित की गई। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और डीआरपीएसई के लगभग सभी सदस्यों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया और प्रदर्शित खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की सराहना की।

पुणे में आयोग के पहले फ्रेंचाइज़ी शोरूम खादी इण्डिया का उद्घाटन

आयोग ने ऐतिहासिक शहर पुणे में इतिहास बनाया

लोगों के दिलों में स्थान बनाने के पश्चात्, एक नवीन पहल के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हयात होटल विमान नगर, पुणे के समीप वसाकोन वेईकफील्ड चेम्बर्स, शोरूम नं.2 बी में अपने पहले फ्रेंचाइज़ी शोरूम का उद्घाटन कर खादी को बड़े पैमाने पर विस्तार प्रदान करने लिए तैयार है|

उद्यम (वेंचर) की इस नवीनतम श्रृंखला की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रत्येक द्वार पर खादी उपलब्ध कराना हमारा मिशन है और आज यहां पहले फ्रेंचाइजी का उद्घाटन इस दिशा में एक छोटी सीपहल है। हम प्रत्येक जिले में एक वास्तविक बिक्री नेटवर्क लाने की योजना बना रहे हैं। इस दिशा में प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। हमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुडुचेरी, गोवा और

कोलकता जैसे बड़े मेट्रो शहरों के अतिरिक्त, यहाँ तक कि दुबई से फ्रैंचाइज़ी बिक्री के लिए खादी इंडिया आउटलेट शुरू करने में रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि "पिछले कुछ वर्षों में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी ने मन की बात के माध्यम से खादी को बढ़ावा दिया है जिससे खादी की मांग, खादी विगत वर्षमें 15.1 करोड़ रुपए बढ़ी है और वर्ष 2016-17 के दौरान 2005 करोड़ रुपए बिक्री हुई,जो कि 33 फीसदी की बढ़ोतरी है। खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में कुल 51,997 करोड़ रुपये का आश्चर्यजनक आंकड़ा और देश में यह बहुत बड़ा आपूर्ति आधार है। हमें अगले 3 सालों में खादी उत्पादन में ५ गुना वृद्धि द्वारा 6000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है,जिससे करीब 20 लाख तक अतिरिक्त अनुमानित रोजगार सृजन होगा।"

तत्कालीन केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी, एमएसएमई ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला वाधवान के साथ 20 अगस्त, 2017 को शक्ति-महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण कार्यक्रम समारोह का उद्‌घाटन किया।

उच्च श्रेणी के उपभोगताओं को गुणवतायुक्त उत्पाद प्रदान करने और खादी हेतु ग्लोबल बाजार विकसित करने एवं अपने कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कम्पनियों जैसे रेमंड, अरविंद मिल्स लि., ए.बी.एफ.आर.एल. के साथ समझौता किया है एंव ओएनजीसी, रेलवे, आरईसी, स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, एन टी पी सी, एयर इंडिया, जे.के. सिमेंट जैसे पीएसयू के साथ अनुबंध किया है।

इस अवसर पर श्री अनिल शिरोले, माननीय सदस्य संसद, ने खादी की प्रासंगिकता और गुणवत्ता पर चर्चा की। उन्होंने पुणे में इस देश के कपड़े खादी को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

शोरूम के मालिक श्री सौरभ चटर्जी ने कहा कि "खादी और ग्रामोद्योग आयोग की छत्रछाया में फ्रेंचाइजी बिक्री केंद्र खोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इससे मेरे सपने साकार होंगे।"

इस कार्यक्रम में संसद सदस्य श्री अनिल शिरोले और महाराष्ट्र सरकार विधान सभा सदस्य श्री जगदीश मुलिक तथा महाराष्ट्र खादी और ग्रामोद्योग मंडल के अध्यक्ष श्री विशाल चोर्डिया ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

इस फ्रेंचाइजी शोरूम में केवल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादों की ही बिक्री की जाएगी, जिन पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी खादी मार्क विनियम, 2013 के अनुसार खादी मार्क लगा हो, जिन उत्पादों पर इस प्रकार खादी मार्क नहीं लगाया गया है तो ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं की जाएगी।

दक्षिण भारत में पहले और देश में दूसरे खादी इंडिया फ्रैंचाइजी का तिरुवल्ला में उद्घाटन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दक्षिण भारत में पहली और देश में अपनी दूसरी फ्रैंचाइजी का उद्घाटन तिरुवल्ला में 24 अगस्त, 2017 को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री एस. श्रीसंत ने किया। इस फ्रैंचाइजी के उद्घाटन कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों ने भाग लिया। यह शोरूम ठुकलासरी जंक्शन पर स्थित है।

24 अगस्त 2017 को, केरल के गांधी श्री के. केलप्पन की 128 वीं जयंती भी थी, वह केरल के खादी और सर्वोदय आंदोलन में अग्रणी रहे थे। उन्होंने खादी बोर्ड के अंतर्गत कई बुनाई केन्द्र, ग्रामोद्योग के आउटलेट और खादी बुनकर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। उन्होंने तवनौर में ग्रामीण संस्थान की भी स्थापना की।

इस नए स्टोर में खादी कपड़े, खादी रेशम साड़ी, ड्रेस सामग्री, चादरें, स्कार्फ, रेडीमेड शर्ट, धोती और अन्य प्रकार के परिधान उपलब्ध होंगे।

केरलवासी अब देश के विभिन्न हिस्सों के खादी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच सकते हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, 'मन की बात' के जरिए देश के लोगों से खादी खरीदने के लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं। केरल में खादी उत्पादों का मूल्य और गुणवत्ता को समझने वाले उपयोगकर्ता काफी बढ़ रहे हैं।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय पूनी संयंत्रों के कामकाज की समीक्षा

15 सितंबर 2017 के बाद आयोग के विभागीय बिक्री केंद्र (डीएसओ), परीक्षण रिपोर्ट के साथ खादी संस्थाओं से खादी वस्त्र उत्पादों को स्वीकार करेंगे- यह बात आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आयोग मुख्यालय में 11-12 अगस्त, 2017 को आयोजित बैठक में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार संबंधित केंद्रीय पूनी सयंत्रों से परीक्षण रिपोर्ट के साथ ही सरकारी विभागों को बड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाएगी। इस बैठक में आयोग के सभी छह केंद्रीय पूनी संयत्रों के परियोजना प्रबंधक, आयोग के वित्त सलाहकार, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विपणन), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी), और खादी निदेशालय के निदेशक, आरआईडी के निदेशक ने भाग लिया।

आयोग के अध्यक्ष ने पूर्व में ही प्रत्येक केंद्रीय पूनी संयत्रों की गतिविधियों एवं कार्यों तथा सीएसपी में रोविंग के लागत/कीमत/मूल्य निर्धारण प्रणाली का अध्ययन करने लिए दौरा किया था । उन्होंने 8 अगस्त 2017 से 10 अगस्त, 2017 तक 3 केंद्रीय पूनी संयत्रों- चित्रदुर्ग, कुत्तूर और त्रिचुर में स्थित सीएसपी का दौरा किया, जिसे खादी संस्था-"केरल खादी ग्रामोद्योग एसोसिएशन", त्रिचूर, केरल द्वारा चलाया जाता है, जहाँ उन्होंने उत्पादन की लागत, अपशिष्ट का प्रतिशत, कर्मचारियों की संख्या में कमी, संयंत्र / मशीनरी का रखरखाव, सफाई, कपास की खरीद लागत, जमीन का समुचित उपयोग, पूनी/ रोविंग की लागत, आकस्मिक श्रमिकों की तैनाती, प्रत्येक सयंत्र का उपयुक्त रूप में कामकाज के बारे में तथा प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन पद्धति का स्वरूप, अव्यय में कमी, 100% उत्पादन क्षमता का उपयोग, कपास की खरीद, अधिमानतः ऑनलाइन बाजार प्रणाली का उपयोग और अपशिष्ट पदार्थ, डीजल और बिजली की खपत का पुनर्चक्रण, संयंत्र में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और बायो-मीट्रिक स्टाफ उपस्थिति प्रणाली, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और अन्य संबंधित मुद्दों पर अपने सुझाव दिए।

बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने केंद्रीय पूनी संयत्रों के प्रबंधकों को संयत्रों में सुचारु रूप से कार्य करने के लिए सुझाव दिए जिसमें उचित रूप में रखरखाव करने के लिए मासिक चेकलिस्ट तैयार करना, पूनी की लागत निकालना, तैयार सामान के स्टॉक का रखरखाव करना, पूर्व में ही खादी संस्थाओं से पूनी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सीएसपी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण पोलिसी तैयार करने के अतिरिक्त पिछले वर्ष के खर्च के मुकाबले इस वर्ष 15% तक व्यय को कम करना और अपने कुल कारोबार का न्यूनतम 20% लाभ अर्जित करने सम्बंधित सुझाव शामिल थे।

केंद्रीय पूनी संयत्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीएसपी को बुनियादी सुविधाओं, गोदामों, कार्डिंग मशीनों, फ्रेम आदि जैसे जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। आम जनता से अपील के लिए, प्रत्येक केंद्रीय पूनी संयत्रों में एक समान खादी इंडिया का "लोगो" लगाने और हर संयंत्र में एक प्रमुख स्थान पर माननीय प्रधान मंत्री का संदेश प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया।

इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष ने विभिन्न ऋणदाताओं की स्थिति की भी समीक्षा की। अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीएसपी को बुनियादी सुविधाओं जैसे गोदामों, कार्डिंग मशीनों, फ्रेम आदि की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार देने का आश्वासन दिया गया।

आयोग के अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि सीएसपी से प्राप्त अपशिष्ट कचरे का पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए और अच्छे फाइबर का उपयोग मोटे रेविंग के उत्पादन में किया जाना चाहिए। इस मोटे रेविंग का उपयोग मोटी गुंडी की कत्ताई करने के लिए किया जा सकता है और जिसे स्मारिका के रूप में बेचने के लिए हेरिटेज चरखा संग्रहालय, नई दिल्ली और अन्य पर्यटन स्थलों में रखा जा सकता है।

श्री सत्यपाल, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि विभिन्न प्रकार के खरीद के बजाय सूती खरीद के लिए "पैरामीटर" की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रकार के खरीद के बजाय पैरामीटर के अनुसार सूती की खरीदी करने हेतु संभावनाओं का पता लगाया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि अधिशेष भूमि का उपयोग हनी मिशन के लिए किया जायेगा इसके लिए इस भूमि में तुलसी और सहजन (ड्रमस्टिक) के पौधे लगाये जाएगें और इसके लिए केंद्रीय पूनी सयंत्र, सिहोर और चित्रदुर्ग को एमटीडीसी, दिल्ली द्वारा मधुमक्खी कालोनियों के साथ मधुमक्खी बक्से प्रदान किये जायेंगे। आयोग के निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) डॉ. एस. ग्रीप, जो एक योग्य कृषि वैज्ञानिक भी हैं, को फ्लोरा और फ्यूना मधुमक्खी का सृजन करने हेतु वैज्ञानिक तरीके से इसकी रुपरेखा (ब्लू प्रिंट) तैयार करने के लिए संयंत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि वे पूरे वर्ष में उच्च गुणवत्तायुक्त वाले मधु और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का उत्पादन कर सके।

यह भी चर्चा हुई कि केंद्रीय पूनी संयत्र के औद्योगिक श्रमिकों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए किया जाएगा और आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित/गैर-कुशल कामगारों को अनिवार्य रूप से

सेवानिवृत्त किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब से खादी संस्थाओं से 25% अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के पश्चात ही संस्थाओं को पूनी की आपूर्ति की जाएगी, साथ-साथ दिनांकित (पोष्ट डेटेड चेक) चेक द्वारा 25% भुगतान और शेष 50% धन राशि एमडीए दावों से वसूली की जाएगी। सभी सीएसपी के पास बेहतर सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं जिनको आईआरजी बढ़ाने के लिए अधिकतम स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। खादी संस्थाओं द्वारा भवनों और सरकारी विभागों को नकली खादी की आपूर्ति की जाती है, इस सम्बन्ध में मंत्रालय और अध्यक्ष कार्यालय ने बहुत सी शिकायतें प्राप्त की हैं, इसका खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन संदेहों को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य निदेशक, खादी संस्थाओं को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करेंगे ताकि वे खादी उत्पादों की भवनों को आपूर्ति करने और सरकार के आदेश निष्पादित करने से पूर्व नजदीक के केंद्रीय पूनी संयत्रों के प्रयोग शाला में अपने खादी उत्पादों का परीक्षण करवा लें।

इस अवसर पर केंद्रीय पूनी संयत्रों के परिसर में सफाई बनाए रखने की भी अपील की गयी।

निदेशक (केआरएम) के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 28 जुलाई 2017 को केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, पुणे के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सुझाव दिए एवं पुणे में 2 द्विवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम में आयोग के मधुमक्खी पालन के क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ भाग लिया।

आयोग ने पम्पोर, जम्मू और कश्मीर में ऐतिहासिक प्रशिक्षण स्थल को पुनर्जीवित किया

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017 (पीटीआई): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने जम्मू-कश्मीर के पंपोर जिले में अपने निष्क्रीय प्रशिक्षण केंद्र को पुनर्जीवित किया है, जो आतंकवाद के दौरान दशकों पहले नष्ट हो गया था। इस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जहाँ 1947 में श्रीनगर से लगभग १६ किलोमीटर दूर पंपोर स्थल पर बापूजी गए थे, और चरखा और करघा प्रशिक्षण के लिए चीनार पेड़ के नीचे बैठे थे। इस पर जानकारी देते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि "इसे 1990 में चरम आतंकवाद के दौरान नष्ट कर दिया था, हमने पंपोर में बहु-उद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र को पुनर्जीवित किया और उसमें चरखे तथा करघे भी स्थापित किये गए हैं तथा

इसके माध्यम से नरेन्द्र मोदी सरकार के शांति संदेश का प्रसार किया गया है। आगे, अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसके माध्यम से और नरेन्द्र मोदी सरकार के संदेश का प्रसार करेगा, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक-दूसरे को गले लगाकर और "गोली और गाली" (बंदूकें और गालियां) को उपयोग में नहीं लाने का संकल्प लिया था।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पम्पोर का विशेष महत्व है क्योंकि 2 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने

इस जगह का तीन दिन दौरा किया और वहां पर एक चिनार वृक्ष के पास बैठकर चरखा और करघा पर प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा, "वहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर चिनार के वृक्ष हैं।" आगे उन्होंने यह भी कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रशिक्षण केंद्र भी उसी स्थान पर बनाया गया था। श्री सक्सेना ने कहा कि आयोग छह महीने के भीतर, कार्यक्रम के प्रशिक्षण को पूरा करेगा और उसी स्थान पर खादी इण्डिया आउटलेट स्थापित करेगा।

समारोह में जम्मू और कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा उपस्थित भी थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस राज्य में पहली बार एक सौर चरखा स्थापित किया गया।

श्री सक्सेना ने कहा कि सिलाई और बुनाई के लिए सोलर चरखा उपयोग में लाने के लिए एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जायेगा और इस प्रशिक्षण को प्रधान मंत्री के ग्रामीण आवास योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ १०० मधुमक्खी बक्से भी स्थापित किये गए हैं तथा चरखा स्थापित करके सिलाई और बुनाई कार्य शुरू हो गया है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब यहाँ के निवासी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि लंबे समय बाद यहाँ पर लोगों का हुजूम था।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अवनिस्सेरी ग्राम पंचायत का दौरा किया, जो केरल में भाजपा द्वारा संचालित एकमात्र पंचायत है। केवीआईसी ने रोजगार सृजन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू किया है।

31 जुलाई 2017 को आयोग के कनाट प्लेस, नयी दिल्ली स्थित खादी इंडिया आउटलेट को पधारने और राष्ट्रीय वस्त्र खादी को संरक्षित करने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर का धन्यवाद।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम तथा खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम पर पश्चिम क्षेत्र आंचलिक समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम तथा खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम पर पश्चिम क्षेत्र आंचलिक समीक्षा बैठक आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.एच. अनिल कुमार की अध्यक्षता में 24 अगस्त, 2017 को आयोग के राज्य कार्यालय, अहमदाबाद में संपन्न हुई।

बैठक में आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पश्चिम क्षेत्र श्री वाई.के.बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी श्री डी. धनपाल, निदेशक, पीएमईजीपी श्रीमती पी.एम. जोगलेकर, राज्य निदेशक, गुजरात एवं महाराष्ट्र श्री एस.जी. हेडाऊ, निदेशक नागपुर श्री आर.आर. गजभिये, उप निदेशक प्रभारी, गोवा श्री एस एस तांबे के अलावा गुजरात सरकार और बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कालीकट में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता अभियान-सह-लोक शिक्षा कार्यक्रम

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना तथा अन्य सरकारी विभागों की स्वरोज़गार योजना पर जागरूकता अभियान- सह- लोक शिक्षा कार्यक्रम दिनांक 9 अगस्त, 2017 को ग्राम पंचायत, कालिकट, साउथ अंडमान में आयोजित किया।

यह कार्यक्रम उद्योग और कृषि निदेशालय, ए.एच.और वी.एस. विभाग, मत्स्यपालन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, एन.वाय.के.एस., बैंक तथा पी.आर.आई.एस. के सहयोग से आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य -प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक प्रसार करना, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम में सम्बंधित क्षेत्र से भावी 53 उद्यमी उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत,कालीकट से श्रीमती आशना मजीद, प्रधान ने इस कार्यक्रम के प्रति संतोष व्यक्त किया एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से स्व रोजगार हेतु बेरोजगार युवाओं को प्रेरित करने तथा उन्हें दिशानिर्देश देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अंडमान और निकोबार खादी और ग्रामोद्योग मंडल की सराहना की।

इस कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के आई.पी.ओ. श्री अरूप मजुमदार, उद्योग विभाग के आई.पी.ओ. श्री एस.के. बिस्वास, मत्स्य निदेशालय के मत्स्य अधीक्षक कुमारी ग्लोरी राव, कृषि निदेशालय के श्री कन्हया लाल प्रसाद, ए.एच. एवं वी.एस. निदेशालय के एस.वी.ओ. डॉ. के.मोहम्मद तथा एन.वाय.के.एस. के जिला युवक समन्वयक श्री कुंदन लाल इत्यादि ने अपने विचार व्यक्त किये|

आयोग मुख्यालय ने मनाया 71 वां स्वतंत्रता दिवस

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 15 अगस्त 2017 को देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ 71 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आयोग की वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश ने आयोग मुख्यालय मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ध्वजारोहण समारोह में आयोग के वरिष्ठ आधिकरियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

इसी देशभक्ति भावना के साथ आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों और खादी और ग्रामोद्योगी मंडलों में भी स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम के रूप में मनाया गया।

आयोग मुख्यालय में आयोग की वित्तीय सलाहकार ने अपने संबोधन में कहा कि खादी, देश के स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी है। गांधीजी ने स्वदेशी आंदोलन को खादी का पर्याय बनाया। उन्होंने, इसे एक सामाजिक समतुल्य सादगी के रूप में बढ़ावा दिया और खादी को देश का वस्त्र बना दिया। श्रीमती उषा सुरेश ने कहा, हमें गर्व है कि देश स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात् भी इस परंपरागत वस्त्र से संबद्ध रहा है और है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में लाखों कारीगरों, उद्यमियों और बेरोजगार युवाओं को मजदूरी के साथ रोजगार प्रदान करने का एक प्रमुख संगठन है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्तायुक्त उत्पाद वितरित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के समेकित विकास में अपना योगदान देने के लिए हमेशा प्रयासरत्त रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और बहुत कुछ हासिल किया जाना है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य पाल ने ७१ वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिशों के साथ युद्ध किया। उन्होंने आगे कहा कि 'खादी' परंपरागत रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा वस्त्र है और आज, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण कारीगरों और युवाओं के लिए खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के प्रचार और विपणन करने में उन्हें आय का एक स्थाई स्रोत प्रदान करने में सबसे आगे रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस.राव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यस्थल पर और व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, संगठन सोशल नेटवर्किंग

प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि से जुड़ा हुआ है, जिससे संगठन को अधिक कुशल तरीके से सूचना का प्रसार करके संचार और उत्पादकता में सुधार करने की अनुमति मिलती है। सोशल मीडिया पर उपस्थित होने से ग्राहक प्रतिधारण में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। संगठनों के लिए सोशल मीडिया संभावित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें विभिन्न सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्मों में शामिल होने और उन्हें संचालित करना सीखने के लिए संकल्प लेना चाहिए।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाय.के. बारामतीकर ने कहा कि आयोग ने खादी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कीं हैं। खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 'स्वराज से सूरज तक' मार्गदर्शन की भावना है। हम सभी को हर स्वतंत्रता दिवस पर कुछ नई पहलों को शुरू करने और उन्हें पूरा करने और अगले स्वतंत्रता दिवस पर इसकी समीक्षा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए । यह संकल्प हमारा व्यक्तिगत मिशन होना चाहिए। यह हमारे प्रयासों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा और यह नियत करने में सहायक होगा कि आने वाले वर्ष में हम अपने कार्यों से वहां कैसे पहुँच सकते हैं।

आयोग के निदेशक, बजट और वित्त, श्री बाबुल मंडल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक राष्ट्र निर्माण करना केवल राजनीति का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागृति का हिस्सा भी है, एक ऐसा परिवर्तन जो मायने रखता है। हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि अपने संगठन के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण और कल्याण करने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सपने बड़े होने चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे। आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे।

आयोग के निदेशक, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्रीमती पी. एम. जोगलेकर ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के विकास में महिला उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप में सुदृढ़ बनाने

के लिए खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में महिला सशक्तीकरण किया गया है। महिलाएं राष्ट्रीय विकास कार्य प्रणाली में तेजी से भाग ले रही हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्र के विकास के विजन को पूरा करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को अपना सबसे अच्छा समर्थन दिया है।

जब आदिवासी महिलाओं ने रैंप पर अपना जौहर दिखाया:

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नर्मदा घाटी में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय शुरू किया

इंदौर: उत्पादन, बिक्री और रोजगार के बढ़ाने की दिशा में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्रों में खादी गतिविधियों को शुरू करने के लिए केंद्र का उद्घाटन करने के पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह नर्मदा घाटी में एक नई शुरुआत है एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दूरस्थ क्षेत्रों में करघा और अधिकतम चरखों का संवितरण किया ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। "नर्मदा घाटी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए अधिकतम संख्या में रोज़गार का निर्माण करना हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि ओंकारेश्वर के पिछले दौरे के दौरान, मैंने इस क्षेत्र की महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए खादी उत्पादन केंद्र खोलने का वादा किया था, और आज नया केंद्र 45 चरखों और 60 प्रशिक्षित कारीगरों से सुसज्जित है, पर्याप्त प्रशिक्षण और पारिश्रमिक के साथ, आयोग की आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त संस्था-माल्वा भील सेवक संघ को, इस केंद्र को चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। "मंत्रालय द्वारा निर्धारित खादी उत्पादन से संबंधित लक्ष्यों और प्रोत्साहनों को लागू करने के अलावा हम खादी संस्थाओं के गठन और नवीकरण के लिए इस क्षेत्र

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 27 अगस्त 2017 को जम्बदी हैपसी, इंदौर में एक पीएमईजीपी इकाई - बालाजी हर्बल्स का उद्घाटन किया। यह इकाई 25 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित की गई है, और 16 स्थानीय लड़कों और लड़कियों को रोजगार उपलब्ध कराएगी।

में युवाओं को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।"

खादी उद्योग की रीढ़ की हड्डी के रूप में महिला कारीगरों की तुलना करते हुए श्री सक्सेना ने आगे कहा कि यह, महिलाओं कारीगरों का दृढ़ संकल्प है कि खादी प्रतिदिन नए मील का पत्थर हासिल कर रही है।

"सभी 45 महिला कारीगर, उचित रूप में प्रशिक्षण लेने के बाद, यह अन्य आदिवासी महिलाओं के लिए वास्तव में एक आदर्श होगी। निरंतर चरखों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, हमने कार्यकारी एजेंसी को चरखा की क्षमता 100 तक बढ़ाने के लिए कहा है, जो जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "मैंने अभी तक अपने जीवन में ऐसा आत्मविश्वास नहीं देखा है, जैसाकि इन जनजातीय महिलाओं ने अपने रैंप करते वक्त प्रदर्शित किया। चूंकि नर्मदा घाटी में विशाल वनस्पति फ्लोरा तथा फ्यूना हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यहां जल्द ही मधुमक्खी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, ताकि यहां स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर और आय के अवसर में वृद्धि हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, "हम खादी को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हम हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी के मिशन और हमारे कुशल कारीगरों के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं"। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे स्थानीय विधायक और महिला सरपंच भी शामिल थे।

ओमकारे-श्वर की खादी महिला कारीगरों ने रैंप पर अपना जलवा दिखाया, तब उनके आत्मविश्वास ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नर्मदा घाटी में 27 अगस्त, 2017 को आयोग द्वारा एक नये अध्याय की शुरूआत की गई।

हैदराबाद में खादी पर चर्चा
दिनांक 27 अगस्त, 2017

आयोग की वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में आंचलिक समीक्षा बैठक संपन्न

मुंबई, 20 जुलाई 2017: विभिन्न खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों के प्रगति की समीक्षा के लिए, एक बैठक आयोग की वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारिओं के साथ आयोग मुख्यालय, मुंबई में आयोजित हुई। सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारिओं ने क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं, नीतिगत फैसलों और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न बैठकों में विभिन्न प्रस्तुतियों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रकृति के विभिन्न मुद्दों के बारे में सूचित किया गया। बैठक के दौरान सभी आंचलिक क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में क्षेत्र की प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गयी।

बैठक में विभिन्न मुख्य मुद्दों जैसे- खादी संस्थाओं द्वारा समयबद्ध एमडीए दावों को गैर-अपलोड करना, पीएफएमएस के तहत एक एमआईएस पोर्टल विकसित करके खादी सेक्टर को ऑनलाइन बनाना, रुग्ण संस्थाओं के मुद्दों, खादी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन जारी करने की स्थिति, खादी गतिविधियों को शुरू करने हेतु आयोग के साथ पंजीकृत नए खादी संस्थाओं के मुद्दे, सभी पंजीकृत खादी संस्थाओं के पुनर्गठन, सीएसपी से खादी संस्थाओं को पूनी की आपूर्ति से सम्बंधित मुद्दे, और अन्य सरकारी एजेंसियों से स्लिवर आपूर्ति आउटसोर्सिंग के लिए मंत्रालय का प्रस्ताव, स्फूर्ति क्लस्टरों के कार्यान्वयन की स्थिति, स्फूर्ति क्लस्टरों के प्रस्ताव, केआरडीपी गतिविधियों के क्रियान्वयन, लंबित लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति, केआरडीपी कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की गई खादी संस्थाओं की क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए आवंटित धन का उपयोग, केआरडीपी गतिविधियों के तहत ए प्राप्त एनएमसी को नामित करने के लिए (संस्था का नाम / संख्या), पीएमईजीपी गतिविधियों के तहत प्रगति की समीक्षा, पीएमईजीपी इकाइयों का 100% भौतिक सत्यापन आदि पर चर्चा की गई।

बैठक में आयोग की वित्तीय सलाहकार/ तत्कालीन मु. का. आधिकारी सुश्री उषा सुरेश, संयुत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य पाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर क्षेत्र श्री एसपी सिंह, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिण क्षेत्र श्री जी. गुरूप्रसंन्ना, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर क्षेत्र श्री सत्यनारायण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाय. के. बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री डी. धनपाल, निदेशक (वित्त/लेखा परीक्षा) श्री बाबुल मंडल, निदेशक (पीएमईजीपी), श्रीमती पी.एम. जोगलेकर, निदेशक (खादी), श्री जे.के. गुप्ता, निदेशक (आरआईडी), श्री के.बी. राव, उप निदेशक प्रभारी (स्फूर्ति) श्री एस.एस. ग्रीप और उप निदेशक प्रभारी (केआरएम), श्री एसपी खंडेलवाल ने भाग लिया।

सशस्त्र बल जल्द ही पहनेंगे खादी वर्दी

सशस्त्र बल जल्द ही खादी से बने वर्दी पहनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को सेना, नौसेना और वायु सेना में सशस्त्र बलों में कर्मियों द्वारा पहने जाने वाले वर्दी के नमूनों और विशिष्टताओं को भेजा है।

रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "वर्दी की आवश्यक विशिष्टतायें, नमूने के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भेज दिया है।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी के उपयोग और विकास को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है।

केवल सशस्त्र बलों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल, पुलिस, सरकारी अस्पतालों, एयर इंडिया और रेलवे इत्यादि में खादी का उपयोग किया जा रहा है इन विभागों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है|

एयर इंडिया के चालक दल के सदस्य पहले से ही खादी वर्दी पहन रहे हैं। विगत वर्ष प्रधान मंत्री के विदेशी यात्राओं में से एक यात्रा के दौरान पहली बार एयर इंडिया के चालक दल ने खादी वर्दी पहनी थी।

इसका उद्देश्य - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन को साकार करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है।

माननीय प्रधान मंत्री ने पूर्व में ही और अपने मन की बात में लगातार खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी कहा हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सरकारी अधिकारियों को खादी वर्दी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के संपर्क में है।

साभार: टाइम्स

आयोग के बहु उद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र, त्रिचुर में तुलसी के पौधे का रोपड़ करतीं हुई महिला कर्मचारी

फैशन के बीच खादी हुई हिट, जल्द ही पेरिस, दुबई में स्टोर खुल सकते हैं

3 अगस्त 2017 बीटी समाचार द्वारा

पिछले 3 वर्षों में 286 नये स्टोरों के अलावा, अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लाउंज फॉर्मेट स्टोर्स के साथ प्रयोग कर रहा है जिसे 'खादी इंडिया लाउंज' नाम दिया गया है, और जो खादी फैब्रिक के उच्च फैशनपरक उपभोक्ताओं की रूचि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

खादी अब छाया में रहने वाली वस्तु नहीं है, वह मजबूत, आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है, अपने फैशनेबल फैशन सर्किलों में ब्रांडिंग कर रही है और यह फ़ैशनिस्ट की वार्डरॉब में लंबे समय तक रह रही है।

इस वर्ष के अंत तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पेरिस और दुबई में अपने पहले वैश्विक स्टोरों की देखरेख एक आक्रामक गति से अपनी विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

"हाल ही में देखा गया है कि हमारे प्रधान मंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के कारण खादी ने विकास की नयी ऊंचाईयों को छूकर उल्लेखनीय वृद्धि की है।

" केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उन्होंने न केवल खादी को लोगों के लिए एक खास फैब्रिक बनाया है- बल्कि विशेषकर उनकी अपील के साथ इस मिलियन वर्ष, खादी भी देश में सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता का एक मॉडल बन गयी है।

प्रधान मंत्री के आधिकारिक वाहक एयर इंडिया वन के कर्मचारियों को खादी फैब्रिक के ड्रेसिंग के बाद, खादी अब सलमान खान, अक्षय कुमार और सोनम कपूर जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी जुड़े रही है। फैशन डिजाइनर रितु बेरी को मोदी सरकार द्वारा केवीआईसी के साथ इकोनिक डिज़ाइनर के रूप में जोड़ा गया है और खादी मार्क अधिदेश - एक परचित कॉटन खद्दर खादी ब्रांड के रूप में विकसित हो रहा है।

वर्ष 2016 में रितु बेरी के अनन्य खादी संग्रह 'विचारवस्त्र' ने 78 लाख रुपए का कारोबार किया था और इस वर्ष भी एक नए विचार के साथ एक नया कलेक्शन तैयार किया जा रहा है।

मोदी प्रभाव

वर्ष 2014 के बाद से, खादी कपड़े की बिक्री करीब 70 प्रतिशत बढ़ गई है और विभाग ने खादी को बढ़ावा देने के लिए न केवल भारत में एक ब्रांड के रूप में

बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खादी की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा रूचि लेते हुए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले वित्त वर्ष में 1,510 करोड़ रुपये के मुकाबले 2016-17 में 2,005 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की थी, केवीआईसी ने 2018-2019 के अंत तक 5000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

कॉर्पोरेट से प्राप्त बड़े आपूर्ति आर्डर खादी की सफलता की कहानी का एक हिस्सा हैं। जबकि ओएनजीसी, एयर इंडिया, भारतीय रेलवे और अन्य संगठनों ने केवीआईसी के आदेश दिए हैं, आईआईटी बॉम्बे और भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज जैसे संस्थान भी अपने वार्षिक दीक्षांत समारोहों के लिए केवल खादी गाउन और शॉल का उपयोग करने के लिए आगे आये हैं।

इस बैंडविगन में शामिल होने के कारण, यहां तक कि निजी ब्रांड कपड़े ढंकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अरविंद लिमिटेड ने केवीआईसी से 40 मिलियन अमरीकी डालर का 1 मिलियन मीटर के कपड़े का ऑर्डर करने का वादा किया है और इसे खादी डेनिम संग्रह के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल करने की योजना है।

रेमंड्स, एलन सॉल्ली और टर्टल जैसे प्रमुख ब्रांड भी खादी के साथ हाथ मिला रहे हैं।

सक्सेना ने कहा, "हम कंपनी को अपने कपड़ा का चयन करने और कपड़े को फैशनेबल और व्यावसायिक

रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं।"

रेमंड ने पहले ही अपने एक मिश्रित संग्रह के लिए दो साल की अवधि में 6 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है।

पिछले 3 वर्षों में 286 नये स्टोरों के अलावा, केवीआईसी अब लाउंज फॉर्मेट स्टोर्स के साथ प्रयोग कर रहा है जिसे 'खादी इंडिया लाउंज' कहा जाता है, जो कि उन्नत और विशेष फैशनपरक ग्राहकों को लक्षित करता है।

पहले चरण में इन लाउंजों को दिल्ली, मुंबई और जयपुर में 25 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया गया है। वर्ष के अंत तक भोपाल, गोवा और लखनऊ में इसी तरह के स्टोर स्थापित किए जाएंगे।

स्रोत: moneycontrol.com

अखिल भारतीय केवीआईसी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा

अखिल भारतीय केवीआईसी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की 26 वीं वार्षिक आम बैठक 19, अगस्त 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ढेबरभाई हॉल, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई में संपन्न हुई।

बैठक में मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम, वाराणसी, मेरठ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री के. के. गुप्ता और संचालन सचिव श्री एन एन लालदास द्वारा किया गया। बैठक में कुछ राज्यों के प्रबंध समिति के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक में आयोग के उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस. राव और श्री वाई.के. बारामतीकर ने भी भाग लिया, जिन्होंने प्रतिभागियों को केवीआईसी के स्तर पर चल रहे कार्यों खासकर पेंशनरों और परिवारिक पेंशन से संबंधित मुद्दों के मामले के बारे में बताया।

एसोसिएशन के प्रबंध समिति की सदस्य कु. दवे द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना के साथ बैठक का शुभारम्भ हुआ, तत्पश्चात सदन ने वर्ष के दौरान दिवंगत 42 पेंशनभोगी सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

एसोसिएशन के 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके 52 पुरुष और 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकीं 9 महिला वरिष्ठ सदस्य पेंशनरों का, बैठक के दौरान सत्कार किया गया। तत्पश्चात्,बैठक में सूचीबद्ध एजेंडा मदों पर चर्चा की गई, सदस्यों के साथ पेंशनरों के लिए मेडिकल सहायता, केवीआईसी द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए संसाधनों के रूप में पेंशनरों की भागीदारी और, वार्षिक खातों आदि जैसे मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सदस्यों पर चर्चा हुई। पहली बार चर्चा किये गए मुद्दों में से एक, कि एक परिवार पेंशनर को एसोसिएशन के सदस्य के रूप में प्रमाण पत्र

जारी कर के उसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भाग लेने वाले सदस्यों ने सबसे ज्यादा मुद्दा, पेंशनरों और केवीआईसी के परिवार पेंशनरों के लिए 7वें वेतन आयोग के विस्तार के बारे में उठाया। कार्यान्वियन में देरी के लिए, सभी सदस्यों ने इस प्रकार अब तक लाभों से वंचित होने के लिए अपने पीड़ा और निराशा व्यक्त की। सभी उपस्थित भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एआईकेपीडब्ल्यूए के उपाध्यक्ष श्री के.डी. कांबले ने मंत्रालय के संयुक्त सचिव, जो वर्तमान में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार के रूप कार्य कर रहे हैं, से संपर्क किया और संयुक्त सचिव ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि मंत्रालय पहले से ही मामले का संज्ञान ले चुका है और अनुकूल निर्णय जल्द ही होने की उम्मीद है, इस बारे में सभी सदस्यों ने संयुक्त सचिव के आश्वासन की सराहना की।

बैठक में सभी प्रतिभागी और सेवा एवं सम्पदा निदेशालय, प्रचार, कैंटीन, सुरक्षा कर्मियों आदि सभी को बैठक के सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया गया।

केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में श्री सत्यनारायण महापूजा

हर साल की भांति इस वर्ष भी परम्पराओं का अनुसरण करते हुए आयोग की सांस्कृतिक समिति ने केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में श्री सत्यनारायण महापूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में कर्मचारियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आयोजित संगीत कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्यपाल भी उपस्थित थे।

आयोग की 647वीं बैठक का कार्यवृत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 647वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2017 को मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आयोग के निम्नलिखित सदस्य:- श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष; श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल); श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल); डॉ. संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्वी अंचल); श्री नारायण चंद्र बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल); श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण और विकास); डॉ. हीना शफ़ी भट्ट, आंचलिक सदस्य (उत्तर अंचल); डॉ. शीला राय, विशेषज्ञ सदस्य (तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण), श्री करनाम सेकर, डीएमडी एवं सीसीओ, भारतीय स्टेट बैंक; श्री बी एच अनिल कुमार, संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.); श्री डी.पी.एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार (सु.ल.म.उ.); श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग उपस्थिति थे।

इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य अधिकारी:-श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग; श्री सत्यपाल, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी; श्री के.एस.राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(प्रमंरोसृका/प्रचार/विपणन/आईटी/एफबीएए); श्री वाई.के.बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प.अं./क्ष.नि./सं.से./वि.प्रौ./एसबीसी/एलआर/प्रशासन); श्री सत्य नारायण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ/उत्तर अंचल/ अध्यक्ष के सचिव); श्री डी. धनपाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी/केपीएम/आरआईडी/ अर्थ-अनुसंधान) भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने सभी सदस्यों का खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 647वीं बैठक में स्वागत किया।

विशेषज्ञ सदस्य (विपणन) ने अपने 4 जुलाई 2017 के ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया था, कि वे अपने पूर्व निर्धारित आधिकारिक बैठकों के कारण आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, जो उसी तिथि पर बहुत पहले निर्धारित किया गया था।

औपचारिक परिचय के बाद, अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ आयोग की 647वीं बैठक निम्नलिखित कार्यसूचियों के साथ शुरू हुई, जिस पर आवश्यक विचार-विमर्श किया गया और निम्नानुसार निर्णय लिए गए: -

कार्यसूची मदें और निर्णय

1.मद संख्या 1: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 29 जून, 2017 को मुंबई में आयोजित 646वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

लिया गया निर्णय:आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 को मुंबई में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 646वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। कार्यवृत्त की पुष्टि के दौरान उठाए गए मुद्दों को अनुलग्नक-I में रखा गया है।

2.मद संख्या 2: दिनांक 31 मई, 2017 को आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 645वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।

लिया गया निर्णय:दिनांक 31 मई, 2017 को आयोजित आयोग की 645वीं बैठक की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विभिन्न निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

3.मद संख्या 3: रु.15 लाख के अतिरिक्त बजट मंजूरी के साथ लॉयन पिक्चर एंड फ्रेम्स (इंडिया) लिमिटेड के "फोटो/पिक्चर फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन" के लिए क्षमता निर्माण निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट।

लिया गया निर्णय: आयोग ने नोट किया कि फोटो/पिक्चर फ्रेमिंग टेक्नोलॉजी पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए लॉयन पिक्चर एंड फ्रेम्स (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल का सुझाव देते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव को जांचने के लिए, उक्त प्रस्ताव को फिर से दोबारा जांचने का निर्देश दिया गया, और इस तरह से इसे आस्थगित कर दिया गया।

कार्रवाई: निदेशक (क्षमता निर्माण)

4. मद संख्या 4: 1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केन्द्रीय कार्यालय को मिलाकर सभी राज्य/ मंडलीय कार्यालयों को प्रदान की गई अधोसंरचनात्मक वस्तुओं के सक्रिय जीवन काल के निर्धारण के लिए नीति को अनुमोदित करने, और २) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 'सबसे स्वच्छ राज्य/मंडलीय कार्यालय' को अंतिम रूप देने हेतु तथा केवीआई से

में 'स्वच्छ भारत अभियान' के कार्यान्वयन हेतु नीति का अनुमोदन करने हेतु सम्पदा और सेवा निदेशालय का नोट। ('स्वच्छ भारत अभियान' के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण आयोग की आगामी 647वीं बैठक में किया जाएगा)

लिया गया निर्णय:आवश्यक विचार-विमर्श के बाद और आयोग विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सुझावों को समायोजित करने के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

A. केंद्रीय कार्यालय, केवीआईसी, मुंबई और केवीआईसी के सभी राज्य/मंडलीय कार्यालयों को प्रदान किए गए विभिन्न अवसंरचनाओं हेतु सक्रिय जीवन अवधि तैयार करने के लिए केवीआईसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रकाशित 'रखरखाव मैनुअल' का अनुपालन कर/अपना सकता है।

B. स्वच्छ भारत अभियान को केवीआईसी के सभी विभागीय बिक्री केन्द्रों, विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों, विभागीय केंद्रीय पूनी संयन्त्रों और सभी खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के कार्यालयों में लागू किया जाना चाहिए।

C. आंचलिक सदस्य (लेकिन एक ही क्षेत्र के नहीं) की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें बाहरी संगठन/राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, 'सबसे स्वच्छ राज्य/मंडलीय कार्यालय/ विभागीय बिक्री केंद्र, विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, विभागीय केंद्रीय पूनी संयन्त्र और खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं' और 'सबसे खराब राज्य/मंडलीय कार्यालय/विभागीय बिक्री आउटलेट, विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, विभागीय केंद्रीय पूनी संयन्त्र और खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं' का चयन करेगी।

D. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 'सर्वाधिक स्वच्छ खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं' का चयन करने के दौरान 'विकास के लिए गांव को दत्तक लेना', प्रधान मंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन, शौचालय आदि का निर्माण आदि पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

E. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान को अपनी सारी गंभीरता से लागू किया गया है, उपर्युक्त समिति कार्यालयों/इकाइयों/ केन्द्रों/संस्थाओं पर दंड लगाने का निर्णय भी ले सकती है, जो कि 'सबसे खराब राज्य/ मंडलीय कार्यालय/ विभागीय बिक्री आउटलेट, विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, विभागीय केंद्रीय पूनी संयन्त्र और खादी एवं ग्रामोद्योग संस्था' होंगे और 'सबसे स्वच्छ राज्य/ मंडलीय कार्यालय/ विभागीय बिक्री केंद्र, विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, विभागीय केंद्रीय पूनी संयन्त्र और खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं' को विजेता के रूप में (1 लाख रुपये के पुरस्कार के साथ) को उचित रूप से सम्मानित किया जाएगा।

F. उद्देश्यात्मक मूल्यांकन के लिए मापदंड, सम्पदा और सेवा निदेशालय द्वारा तत्काल तैयार किया जाना चाहिए और केवीआईसी के सभी कार्यालयों और संस्थानों को इससे अवगत किया जाना चाहिए।

G. संयुक्त सचिव, एमएसएमई ने सूचित किया कि एमएसएमई ने "स्वाभेता अभियान" पर एक वेब पोर्टल बनाया है, जहां सभी एमएसएमई विभागों की तस्वीरों को स्वाभाविक अभियान से पहले और बाद में अपलोड किया जाना है।

- निदेशक (सम्पदा और सेवा)

5.मद संख्या 5: समूह 'ए' अधिकारियों के संबंध में एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के बारे में विचार करने हेतु प्रशासन के निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट।

लिया गया निर्णय: प्रशासन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नोट पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

A. निम्न अधिकारियों को निम्नानुसार एमएसीपी को स्वीकृति दी गई है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्रस्तावित एमएसीपी	पीबी + ग्रेड वेतन प्रभावी तिथि-
1.	श्री उत्कल केसरी,	उप निदेशक	3रा	Rs.15600-39100 + GP RS.7600/-06.05.2015
2.	श्री ए एल मीना,	निदेशक	2रा	Rs.15600-39100 + GP RS.7600/- 12.02.2016 to 31.05.2016
3.	श्री के जे भोसले,	निदेशक	2रा	Rs.15600-39100 + GP RS.7600/- 15.02.2016 to 31.05.2016
4.	श्री राधाकृष्णन वी,	उप निदेशक	3रा	Rs.15600-39100 + GP RS.7600/-01.05.2014

B. चर्चा से यह पता चला कि एमएसीपी के मामलों को अत्यधिक देरी से प्रक्रियागत/ स्वीकृत किया जा रहा है, और इस तरह योग्य अधिकारियों को उनके पात्रता की एमएसीपी को अपनी वास्तविक नियत तारीख से वंचित किया जा रहा है। इसलिए, एमएसीपी के लंबित मामलों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाना है, और यह सुनिश्चित किया जाना है कि केवीआईसी कर्मचारियों के एमएसीपी के मामलों को ठीक से प्रक्रियागत किया गया है और पात्र अधिकारियों को नियत तारीख से 6 महीने के भीतर उनकी एमएसीपी प्रदान की गई है।

C. आयोग द्वारा यह भी नोट किया गया था कि सेवानिवृत्त केवीआईसी कर्मचारियों/अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के मामले भी प्रशासन के निदेशालय द्वारा जरूरी/गंभीर ध्यान देने की जरूरत होती है, और उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

D. वे अधिकारी, जो उपरोक्त बिन्दु बी और सी का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं कर रहे हैं, वे उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह होंगे, और और सख्त अनुशासनात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।

E केवीआईसी के कर्मचारियों/ अधिकारियों को 'एमएसीपी' के मामलों को मंजूरी देने के लिए, आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया।

कार्रवाई: 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशा. एवं मानव संसाधन)
2. उप निदेशक (प्रशा. एवं मानव संसाधन)

6. मद संख्या 6: निदेशालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत नोट; जिसमें श्री के वी दलाल, सहायक निदेशक-I I (एबीएफपीआई) द्वारा रू.1,62,402/-, और श्री रामजी अस्थाना, सहायक निदेशक-I I (एचएमपीएफआई) द्वारा रू.93,710 / - के किए गए बाह्य रोगी चिकित्सा उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आयोग के अनुसमर्थन की मांग की गई है।

लिया गया निर्णय:संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.) ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि उपर्युक्त कार्यसूची जैसा एक मामला पहले ही 29 जून 2017 को आयोग की 646 वीं बैठक में लिया गया जिसमें आयोग ने बाह्य रोगी चिकित्सा उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया जिससे कि प्रस्तुत किए गए दावों का समय पर/शीघ्र निपटान किया जा सके। इस संबंध में प्रशासन निदेशालय आवश्यक आदेश जारी करेगा।

कार्रवाई: 1. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशा. एवं मानव संसाधन)
2. उप निदेशक (प्रशा. एवं मानव संसाधन)

7.मद संख्या 7: निदेशालय प्रशासन द्वारा प्रस्तुत नोट; जिसमें दिनांक 10.07.2017 को आयोजित डीपीसी की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, श्री एम टी वाकोड़े, निदेशक को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए जारी किए गए आदेश के संबंध में आयोग के अनुमोदन की मांग की गई है।

लिया गया निर्णय:आयोग ने दिनांक 10.07.2017 को आयोजित डीपीसी की बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, श्री एम टी वाकोडे, निदेशक को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिए प्रशासन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया।

उप निदेशक (प्रशा. एवं मानव संसाधन)

8. मद संख्या 8: दिनांक 08.06.2017 को मुंबई में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2017-18) की 2री बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

लिया गया निर्णय:आयोग ने दिनांक 08.06.2017 को मुंबई में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2017-18) की 2री बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्रवाई: सचिव (स्थायी वित्त समिति)

9. मद संख्या 9: अतिरिक्त कार्यसूची

मद संख्या 9.1: केवीआईसी के लिए एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करने अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने में विधि मामले निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि के लिए विधि मामले निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट।लिया गया निर्णय:केवीआईसी के लिए कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने में विधि मामले निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसमर्थन किया गया।

संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.) ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं को इस हेतु संलग्न किया जा सकता

है, और केवीआईसी के राज्य कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए सभी अधिवक्ताओं के पैनल को रद्द कर दिया जाए।

कार्रवाई: निदेशक (विधि मामले)

मद संख्या 9.2: अप्रैल 2017 में रांची में आयोजित अभ्यरण्य कार्यशाला में लिए गए निर्णयों के संबंध में तैयार की गई कार्य योजना के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए पीएमईजीपी के निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नोट।

लिया गया निर्णय: उपर्युक्त नोट पर विचार-विमर्श करते समय, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान विकास) ने सुझाव दिया कि केवीआईसी अधिकारियों की टीम द्वारा 'रेड कॉरिडोर क्षेत्र' में आने वाले झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा का दौरा किए जाने की आवश्यकता है। इस टीम में (a) राज्य निदेशक झारखंड, (b) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी), (c) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामोद्योग) शामिल होंगे जो 'रेड कॉरिडोर क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के इस टीम का नेतृत्व सदस्य पूर्वी अंचल करेंगे।

झारखंड में 'रेड कॉरिडोर क्षेत्र' के विकास के लिए उपरोक्त संक्षिप्त रणनीति की सफलता का मूल्यांकन करने के बाद इसे छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में 'रेड कॉरिडोर क्षेत्र' में कार्यान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।

कार्रवाई: निदेशक (पीएमईजीपी)

मद संख्या 9.3: पीएमईजीपी के निदेशालय द्वारा प्रस्तुत समीक्षा नोट, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही तक दिनांक 21.07.2017 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सामाजिक वर्गों के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धि के बारे में आयोग को अवगत करना।

लिया गया निर्णय: उपरोक्त प्रस्तुत समीक्षा नोट पर चर्चा करते हुए, संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.) द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सामाजिक वर्गों के तहत वर्ष 2008-09 से भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के बैकलॉग के विवरण तैयार किया जाए।

पीएमईजीपी परियोजनाओं की वित्तपोषण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए; और वर्ष 2017-18 के लिए पीएमईजीपी लक्ष्यों को समय पर पूरा करने हेतु बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया को गति देने हेतु, भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि, जो आयोग की बैठक में मौजूद थे, को क्षेत्रों में सभी एलएचओ के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने का अनुरोध किया गया।

कार्रवाई: निदेशक (पीएमईजीपी)

मद संख्या 9.4: गोपनीय

मद संख्या 9.5 : आयोग की 647वीं बैठक में स्व-विवेक से लिए गए

निर्णय लिया गया निर्णय: i.जम्मू-कश्मीर में संस्थाओं के बजट को मंजूर नहीं किया जाना:

आंचलिक सदस्य (उत्तर अंचल) द्वारा आयोग का ध्यान जम्मू और कश्मीर में संस्थाओं द्वारा बजट स्वीकृति के संबंध में सामना की जा रही समस्याओं की ओर आकृष्ट किया । इस संबंध में वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए संस्थाओं हेतु बजट की मंजूरी से जुड़े विभिन्न स्तरों/प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया, और इंगित किया कि जम्मू और कश्मीर में संस्थाओं ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उनके लंबित पड़े लेखापरीक्षा को पूर्ण करने के लिए किए गए अनुरोध के प्रति सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं दिया है, जो कि पांच वर्षों से अधिक लंबे समय से लंबित पड़े हैं। अंत में यह निर्णय लिया गया कि जम्मू और कश्मीर में संस्थाओं (जो सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के अधीन नहीं आते हैं) को दो माह का समय प्रदान किया जा सकता है ताकि वे सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रिया को पूरा कर सकें, और आगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग को कार्रवाई हेतु सूचित करें, जिससे कि वर्ष 2016-17 के लिए उनके बजट को उनके वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जा सके, और वर्ष 2017-18 के लिए बजट को अनुमानित लक्ष्यों पर अनुमोदित किया जा सके।

सदस्य (उत्तरी अंचल) ने जम्मू और कश्मीर के कत्तीनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने कलिए "ऊन बैंक" स्थापित करने हेतु ध्यान आकर्षित किया।

कार्रवाई: निदेशक (लेखापरीक्षा)
निदेशक (बजट)

ii. जम्मू और कश्मीर में गांधी आश्रम की संपत्ति की उपयोगिता:

आंचलिक सदस्य (उत्तर अंचल) द्वारा यह सूचित किया गया

कि जम्मू और कश्मीर में गांधी आश्रम की संपत्ति अप्रयुक्त पड़ी है और इसलिए इसमें अतिक्रमण का भय बना रहता है। इस पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गांधी आश्रम की मातृ संस्था को संपर्क किया जाए जिससे कि उक्त संपत्ति पर आवश्यक विवरण तथा इसकी उपयोगिता के बारे में उनकी योजना पर जानकारी एकत्र की जा सकें। उक्त विवरणों को प्राप्त करने के उपरान्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग मामले की जांच कर सकता है और और जम्मू और कश्मीर में गांधी आश्रम की उक्त संपत्ति के उपयोग के बारे में समुचित निर्णय ले सकता है, जिसमें वहां खादी प्लाज़ा निर्मित किए जाने की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है।

कार्रवाईः निदेशक (खादी)

iii. खादी उत्पादन का मीटर में डाटा संकलन :

सदस्य (मध्य अंचल) ने इस बात पर जोर दिया कि खादी उत्पादन का डाटा संकलन 'मीटर' में किया जाना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करने के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 में अर्थ अनुसंधान निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार विवरणों/ डाटा का भी वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संदर्भ दिया गया और निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

a. खादी उत्पादन पर डाटा संकलित करने के दौरान, अंक वार/वस्त्र वार/मीटर वार मूल्यों के विवरण को दर्शाया जाना
b. संबंधित आंचलिक सदस्य सीएसपी की कॉटन खरीद समिति के सदस्य होंगे
c. कार्यशील हालत में कुल चरखों और करघों की संख्या और बंद पड़े चरखों व करघों की कुल संख्या
d. खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं व खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की राज्यवार मैंपिंग शुरू करना
e. उत्पादवार लक्ष्यों को तैयार करना
f. आगामी पांच वर्षों की अवधि में कारीगरों के आधार को बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार करना।

कार्रवाईः निदेशक (खादी)
निदेशक (ग्रामोद्योग समन्वय)
निदेशक (अर्थ अनुसंधान)

iv. खादी की विभिन्न किस्मों हेतु लागत विवरण को संकलित करना

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी(विपणन) ने अहमदाबाद में माननीय अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न 52 खादी संस्थाओं के साथ आयोजित की गई बैठक में प्राप्त सराहनीय परिणामों के बारे में जानकारी दी जिसमें सभी खादी संस्थाएं अपने कारीगरों को वर्तमान में प्रदत्त मजदूरी रु.5.50 के अतिरिक्त रु.4.50 प्रति हेंक की बढ़ोतरी करने पर सहमत हुए।

उपर्युक्त उपलब्धि पर अधिक चर्चा करते हुए संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय ने उप निदेशक /प्रभारी (सीसीसी)को निर्देश दिया कि खादी की विभिन्न किस्मों के लिए लागत विवरण संकलित करें जिससे वर्तमान में खादी संस्थाओं द्वारा कारागारों को प्रदान किए जा रहे वित्तीय लाभ की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्रवाई – उप निदेशक /प्रभारी (सीसीसी)

V. केवीआईसी के तहत ग्रामोद्योग को पुनर्जीवित करना

विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास) ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित/सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले उपायों की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया।इस संबंध में गहन चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए;

क.स्थानीय संसाधनों के साथ उद्योग स्थापित करने की क्षमता, कच्चे माल की 'क्षेत्र विशिष्ट' उपलब्धता को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण करना।
ख.कार्यशील, बंद पड़े एवं जिन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है ऐसी ग्रामोद्योगी इकाइयों (केवीआई संस्थाएं, आरईजीपी और पीएमईजीपी) को चिन्हित करना।
ग.केवीआईसी के पास उपलब्ध मानव शक्ति की प्रभावोत्पादक परिनियोजन के लिए योजना तैयार करना।
घ.'मिशन मोड' पर ग्राम उद्योगों जैसे शहद, पामगुड़ और बांस का विकास करना।
ङ.'मिशन मोड' के तहत "खाद्य और गैर-खाद्य तेल बीजों" के लिए तेल उद्योग के विकास पर विचार करना।
च.तेल बीज के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए दक्षिण क्षेत्र में

उपलब्ध सुविधाओं को पुनर्जीवित करना जैसा कि सदस्य (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा सूचित किया गया।

छ.ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 'आईसेक' सुविधा की बहाली पर विचार करना जिसे पूर्व में ग्रामोद्योगों के लिए कार्यान्वित किया गया परंतु बाद में बंद किया गया।

ज.क्षेत्रीय कार्यालयों में जीएसटी पर कार्यक्रम/शिविर आयोजन करना और उनको एमएसएमई, मंत्रालय के डाटा बैंक के साथ जुडने के लिए उद्योग आधार ज्ञापन के अधीन पंजीकरण की आवश्यकताओं के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन आने वाले उद्यमियों/खादी संस्थाओं/आरईजीपी इकाइयों/पीएमईजीपी इकाइयों को संवेदनशील बनाना, जिससे उनको 'बूस्टर डोज़' की सुविधा प्राप्त करने में सहायता होगी।

उपरोक्त बिंदुओं पर किए गए विस्तृत विचार-विमर्श को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए संयुक्त सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि एमएसएमई मंत्रालय खादी विकास योजना और 'ग्रामोद्योग विकास योजना' की नई योजनाएं शुरू करने हेतु रूपरेखा तैयार कर रहा हैं।

कार्रवाई – निदेशक (वीआईसी)

vi. एमडीए दावों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाना

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित समय के भीतर एमडीए के दावों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर गहन चर्चा के बाद संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय ने खादी संस्थाओं को अपने एमडीए दावे प्रस्तुत के लिए वर्तमान समय सीमा को एक माह तक बढ़ाने के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। जो खादी संस्थाएं बढ़ायी गयी समय सीमा के भीतर एमडीए दावे प्रस्तुत नहीं करेंगी उनके एमडीए दावों पर आगे विचार किया नहीं जाएगा।

कार्रवाई – निदेशक (खादी)

vii. धारवाड़, कर्नाटक में मंडलीय कार्यालय खोलने के संबंध में

आंचलिक कार्यालय (दक्षिण क्षेत्र) केवीआईसी, बेंगलुरु द्वारा किए जा रहे पत्राचार और सदस्य (दक्षिण अंचल) द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ में मंडलीय कार्यालय खोलने संबंधी मुद्दे के संबंध में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने याद दिलाया कि कर्नाटक के धारवाड़ में मंडलीय कार्यालय खोलने के संबंध में प्रशासन निदेशालय द्वारा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा भेजे गए कुछ पत्रों का जवाब देना है।

कार्रवाई –उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(प्रशासन एवं मानव संसाधन)

Viii. मेरठ में केवीआईसी के मंडलीय कार्यालय का विभाजन करने के संबंध में

मंडलीय कार्यालय, केवीआईसी, मेरठ के अधिकार क्षेत्र अंतर्गत खादी संस्थाओं की कुल संख्या मंडलीय कार्यालय, केवीआईसी, मेरठ में उपलब्ध जनशक्ति की तुलना में कई गुना हैं, अतःमंडलीय कार्यालय, केवीआईसी, मेरठ के विभाजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उचित कार्य योजना/कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए।

कार्रवाई-उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(प्रशासन एवं मानव संसाधन)

ix. निदेशक, मंडलीय कार्यालय केवीआईसी, मेरठ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में

मंडलीय कार्यालय, केवीआईसी, मेरठ के विभाजन पर चर्चा करते समय आयोग की जानकारी में यह लाया गया कि निदेशक (मेरठ) ने उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मध्य अंचल)द्वारा मांगे गए कुछ रिकॉर्ड के लिए उन्हें लिखित रूप से मना कर दिया । आयोग ने निदेशक, मंडलीय कार्यालय, मेरठ के इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार/ अनुशासनहीनता पर गंभीर आपत्ति और नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि उपरोक्त कार्य के लिए निदेशक, मंडलीय कार्यालय, मेरठ के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई-उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(प्रशासन एवं मानव संसाधन)

आगामी बैठक

यह निर्णय लिया गया कि आयोग की 648वीं बैठक और स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 21 अगस्त 2017 को श्रीनगर में आयोजित की जाएगी।

****

सोलर चरखा प्रोजेक्ट - ग्राम खनवाँ, जिला नवादा

*गिरिराज सिंह

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्वावलंबन और देश प्रेम का प्रतीक महात्मा गांधी का चरखा आज 70 साल बाद अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाया। तकनीक और नवाचार की कमी रही। MGIRI, वर्धा द्वारा विकसित सोलर चरखे के मॉडल को अपनाते हुए माननीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने आदर्श ग्राम खनवाँ में मंत्रालय के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ कराया, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए।

आज की तिथि में भारतीय हरित खादी ग्रामोद्योग संस्थान के तहत करीब 30 हजार वर्गफुट क्षेत्र में ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर में खादी की Ginning से लेकर RTW के उत्पादन तक सम्पूर्ण value chain की ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जा रही है और PMEGP के तहत अब तक स्वीकृत (Sanctioned) 700 महिला आर्टिजन में से 520 आर्टिजन के घर पर सोलर चरखा कार्यरत हैं। इस प्रोजेक्ट के impact निम्नलिखित रूप में सामने आये हैं :-

1. वर्तमान सोलर चरखे से ग्रामीण आर्टिजन को 4-5 हजार रुपये प्रति माह की आमदनी हो रही है, जो पूर्व से कार्यरत हस्तचालित NMC मॉडल की तुलना में 3-4 गुना है, जिससे आने वाले दिनों में प्रति आर्टिजन 9-10 हजार रुपये प्रति माह तक आमदनी सुनिश्चित करने की योजना है।

2. सोलर ऊर्जायुक्त उन्नत चरखे के मॉडल से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं/बुनकरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हुआ है। यार्न उत्पादन से लेकर RTW के उत्पादन तक करीब 1100 परिवार इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में ग्रामीण आय में 10-12 करोड़ प्रति वर्ष तक की वृद्धि संभावित है।

3. सोलर चरखा प्रोजेक्ट के 1 चरखे से पूरी value chain में 10 रोजगार (Direct/Indirect) उत्पन्न करने की क्षमता है और इसको देखते हुए खनवाँ में वर्तमान

कार्यरत TPC की सहायक यूनिट के रूप में ट्रेनिंग सेंटर हर 10 हजार की जनसंख्या के क्लस्टर में खोला जा रहा है। वर्तमान में 5 ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत हैं तथा इस वर्ष के अंत तक 8-10 ट्रेनिंग सेंटर कार्यरत हो जाएंगे।

4. खादी का टेक्सटाइल सेक्टर में वर्तमान योगदान 1 प्रतिशत से भी कम है, वहीं हैण्डलूम का योगदान करीब 11 प्रतिशत है। इस प्रकार सोलर चरखे से उत्पादित यार्न, हैण्डलूम सेक्टर के लिए एक अनुपूरक (Supplementary) forward linkage के रूप में काम कर सकता है।

5. यदि भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर (प्रति वर्ष 2 करोड़) और प्रति व्यक्ति 25-32 मीटर प्रति वर्ष कपड़े की आवश्यकता को दृष्टिगत रखा जाए तो सोलर चरखा/करघा के माध्यम से इस प्रत्यक्ष मांग को Cost effective और user friendly सोलर वस्त्र के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

6. आदर्श ग्राम खनवाँ के बाद माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के काकरहिया में भी ट्रेनिंग सेंटर प्रारम्भ किये गये हैं। खनवाँ प्रोजेक्ट की impact analysis को देखते हुए 500 संसदीय क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित सोलर चरखा प्रोजेक्ट को roll out करने की योजना पर काम चल रहा है और जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट के विचारार्थ रखा जाना है, जिसकी पूरी value chain से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

7. सोलर चरखे का यह मिशन वस्तुतः परंपरागत चरखे को सोलर के माध्यम से Green energy के साथ युक्त करते हुए विकेन्द्रीकृत यार्न उत्पादन और RTW वस्त्र उत्पादन तक की पूरी value chain की कई विशिष्टताओं को समाहित किए हुए है, जिसकी ओर बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी तेजी से आकर्षित हो रही हैं। Raymond और डब्ल्यू (w) जैसे ब्रांड का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना इस बात का परिचायक है।

*****

***लेखक सूक्ष्म ,लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं।**

साभार: पत्र सूचना कार्यालय, पी.आई.बी.

हिंदी दिवस पर विशेष लेख

सरलता ही हिंदी को आगे ले जाएगी

*विजय गोयल

पटना में हिंदी दिवस के आयोजन का एक दृश्य

हिंदी के भविष्य को लेकर अक्सर मेरे मन में बहुत से सवाल उठते हैं। आज चारों ओर यह माहौल बनता जा रहा है कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कुछ लोग कहने लगे हैं कि अंग्रेजी न जानने के कारण बच्चे समाज में पिछड़ जाएंगे, सरकारी स्कूल भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से क्यों नहीं पढ़ा रहे? अभी का वातावरण देखते हुए कभी-कभी ये बातें सच लगने लगती हैं।

आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की भरमार हो रही है। हिंदी माध्यम के कारण लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में झिझक रहे हैं। वे अपने बच्चों को टूटी-फूटी इंग्लिश वाले पब्लिक स्कूलों में पढ़ाना बेहतर समझने लगे हैं। जब मैं पहली बार 1996 में सांसद बना था, तब से देखता आया हूं कि संसद का काम, संसदीय समितियों का काम और दोनों सदनों में ज्यादातर भाषण अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी में ही प्रश्न पूछे और उत्तर दिए जाते हैं। ऐसा करने वालों में बड़ी संख्या उन सांसदों की है, जो हिंदी में ही भाषण देकर चुनाव जीतते हैं। मैंने पूरे देश में आज तक किसी को भी अंग्रेजी में भाषण देकर संसद या विधानसभा आते नहीं देखा।

समाज का चलन

जब मैं मंत्री बना और मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचा तो यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ वहां पूरी कार्यवाही हिंदी में हो रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बड़े से

बड़े अधिकारियों और प्रतिनिधियों की बैठकों में भी पूरी कार्यवाही हिंदी में होती है। कई बार प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए भी टोका है कि दक्षिण से आए हुए अफसर भी हिंदी में बोलने की कोशिश क्यों न करें। संसद में जो व्यक्ति जिस भाषा में चुनाव जीतकर आता है, उसको उसी भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। इसी तरह संसद की स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति के सदस्यों से भी बैठक में पहले पूछा जाना चाहिए कि अधिकांश सांसद कौन-सी भाषा में कार्यवाही चाहते हैं? अंग्रेजी में या हिंदी में? फिर उसी हिसाब से समिति की बैठक की कार्यवाही चलनी चाहिए।

लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मंत्रालयों के अधिकारी आते है और अपना प्रस्तुतिकरण सीधे अंग्रेजी में शुरू कर देते हैं। बहुमत में बैठे हुए हिंदीभाषी सांसद शर्माशर्मी में उनसे यह नहीं कह पाते कि आप हिंदी में अपना प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं करते। अंग्रेजी आज स्टेटस सिंबल बन गई है इसलिए कोई बताना और जताना नहीं चाहता कि उसको अंग्रेजी में असुविधा है। पूरा देश इसी तरह चल रहा है। ठीक तरह से अंग्रेजी न आने के कारण लोग अपने आपको छोटा समझते हैं। समाज का चलन भी यही है कि वह अंग्रेजी न जानने वालों को छोटा करके देखता है।

सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में हिंदी की लगातार अवहेलना हो रही है। न्यायपालिका की स्थिति तो और खराब है। कभी-कभी हालत ऐसी हो जाती है कि मुकदमा करने वाला (वादी) और जिस पर मुकदमा चल रहा है (प्रतिवादी), दोनों को ही अंग्रेजी नहीं आती, पर जिरह अंग्रेजी में हो रही है। अनुच्छेद 343 (1) में हिंदी को संघ की भाषा बनाया गया है। इसे गति देने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया, पर इससे भी हिंदी का घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा है।

मंत्रालय में मेरे पास हिंदी में पत्र बनाकर लाने वाले अधिकारी ऐसी क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं, जिसे देखकर मेरे जैसा हिंदी प्रेमी और हिंदी का अच्छा जानकार भी मन ही मन यही सोचता है कि इससे तो अंग्रेजी में लिखा पत्र ही ठीक है। हिंदी में उनको इतना रटाया और पकाया गया है कि वे 'लकीर के फकीर' बन गए हैं। सरकार और पूरी संसद के कामकाज में ऐसी ही भाषा का प्रयोग हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी को बढ़ावा सरल हिंदी के प्रयोग से ही मिलेगा।

शर्म से सिर तब झुक जाता है, जब हम मंत्रालयों में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसा वर्ष में एक बार गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या फिर किसी महापुरुष के मरने पर उसकी जयंती मनाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे हिंदी भी मर रही है, इसलिए साल में एक बार उसकी रस्म अदायगी 'हिंदी दिवस' के रूप में कर दी जाए। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी हिंदी अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है। किसी ने ठीक कहा है कि 'हिंदी को फुटपाथ पर गुजर-बसर करना पड़ रहा है, जबकि अंग्रेजी पांच सितारा होटलों में ऐश कर रही है।' हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाकर देश को जोड़े रखने के लिए मैं हिंदी सिनेमा के सामने नतमस्तक हूं। बॉलिवुड वाले इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं कि भारतवासी चाहे वे उत्तर के हों या दक्षिण के, हिंदी सिनेमा देखना चाहते हैं। यहां तक कि चीन में 'दंगल' फिल्म ने अपार सफलता प्राप्त की। डब होने के बावजूद चीन तक हिंदी तो पहुंच ही गई।

मातृभाषा में पढ़ाई

मुझे शिकायत यह नहीं है कि अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा रही है। अंग्रेजी से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमें देश-विदेश के लोगों से संवाद का मौका मिलता है। पर जब केवल अंग्रेजी बढ़ रही हो और हिंदी की दुर्दशा हो रही हो तो ग्लानि होती है। आज मैं यह सोचने को मजबूर हूं कि यदि देश में एक ही भाषा केवल हिंदी होती तो जो आईएएस अधिकारियों का समूह आज उच्च स्थानों पर बैठा है, उसकी जगह दूसरा समूह होता। हिंदी को बढ़ाने का एक रास्ता यह भी है कि पांचवीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई हो। उसके बाद आगे की पढ़ाई में किसी और माध्यम के प्रयोग की छूट हो। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास ज्यादा बेहतर होगा।

(लेखक संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं)

साभार: नवभारत टाइम्स, मुंबई

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

MILLENNIUM POST | New Delhi | Saturday, 19 August, 2017

mp in focus | 9

Bringing about a sweet revolution

Importance of honeybees in crop productivity and in doubling farmers' income

V.K.SAXENA

Hills, forests, and agriculture land are unique biological wealth that could be converted into economic wealth and a source of livelihood on a substantial basis. These are the best areas for promotion of beekeeping industry for honey production and colony multiplication. In America, farmers and orchardists pay $100 to 150 per bee colony per month to the beekeepers for bee pollination service

Always on the lookout for innovative ideas to change the face of the nation, Prime Minister Narendra Modi recently said along with 'Shwet Kranti' there is also a need to launch 'Sweet Kranti'. The PM's vision is to make India a world leader in the production of honey and beeswax and convince the farmers to increase crop production through cross pollination.

Flowering plants first appeared on earth about 5 to 8 crore years ago. Honeybees are presumed to have evolved from their wasp-like ancestors simultaneously or immediately after the appearance of flowering plants on the earth. This is so, because both flowering plants and honeybees are interdependent. Honeybees use nectar and pollen collected from flowering plants as food and also transfer pollen, the male sperm of the flowers, from one flower to the female part of another flower of the same species. This brings fertilisation in flowers. This cross-pollination results into formation of large quantity of quality seeds and fruits.

Honeybees and forests have co-evolved as one biological unit over millions of years (Representational Image)

HONEYBEES AND ENVIRONMENT

In forests, trees, shrubs, herbs, climbers, weeds etc., flowers provide food to honeybees for a major part of the year. The forests also provide shelter to honeybees. They reciprocate their obligations by offering pollination service, assuring formation of large quantity of seeds, and maintaining genetic diversity in plants. Honeybees are therefore an integral part of forests and their ecology. A healthy forest is an indication of healthy bee fauna in the forests. Thus, honeybees and forests have co-evolved as one biological unit over past millions of years. Hills and mountains are distributed all over the country. Hills and adjacent agricultural belts dotted with a mixture of forests and agricultural land are unique biological wealth that could be converted into economic wealth and a source of livelihood on a substantial basis. These are the best areas for promotion of beekeeping industry for honey production, colony multiplication, and providing bee colonies for pollination of various agricultural crops.

HONEYBEES AND AGRICULTURE

Honeybees are of great importance to farmers for pollination and increasing crop yields, both qualitatively and quantitatively. Agricultural scientists in America have estimated that value of the increased crop yields due to bee pollination is 15 to 20 times more than the value of honey and wax the bees produce.

The ongoing Central projects for increasing crop yields have not been very effective. Vegetable yields per acres are declining; output increase is linked to area expansion.

During 2016-17 India imported edible oil equal to 70 per cent of the home production. A majority of the oil producing crops depend on insect's pollination. A large number of plants are fruitful only when pollen from the flowers from one plant is transferred to the flowers of another plant of the same species to ensure fertilisation. Under present day conditions, honeybees are, by far, the most efficient, reliable, and leading agent in this pollen distribution, most commonly known as pollination.

In the case of highly self-sterile crops, presence of honeybees during the flowering of such crops certainly increases their yields significantly. Some of the crops, benefited by honeybee pollination are: Oil seeds: Mustard, rapeseed, toria, safflower, sunflowers, etc; Pulses: Tur (Arhar), Mung, Urad. Etc; Orchard crops: Apples, Pears, plum, peach, cherry, litchi, citrus, almond, pomegranate, guava etc; Legumes and fodder crops: soybean, broad bean, dwarf bean, alfalfa, berseem, clovers etc; Vegetable seeds: Radish, cabbage, turnip, carrot, onion, cauliflower, gourds etc; Condiment crops: Cardmom, nutmeg, pepper, coriander, etc; Misc: Cotton, coffee.

According to the report of FAO, honeybees play a role in nearly 74 per cent of the world's edible oil production. The value of the increased crop production due to insect

WORLD HONEYBEE DAY

pollinators is worth $ 203 billion. In America, farmers and orchardists pay $ 100 to 150 per bee colony per month to the beekeepers for bee pollination service. In California, Almond orchardists pay about $ 15 crore to beekeepers for bee-pollination service rendered during two months of flowering season. In India, crop yields per hectare of all crops are just 40-50 per cent of the world productivity per acre. Honeybee pollination can play a major role in bridging the gap.

CONSERVATION OF HONEYBEE COLONIES

Over 70 per cent of the several hundred major cultivated crops of the world are dependent on insects for pollination. Physical and chemical changes in the environment have accelerated a crisis of decline in the richness of the species of honeybees and other pollinators. Environmentalists and scientists have been warning that excessive use of insecticides, pollution, resulting into depletion of the population of insect pollinators, is threatening to reduce our total supply of food by 1/3. As a result, 50 per cent of the population of the developing countries could suffer from malnutrition. As honeybees are the most efficient, leading and reliable pollinators to boost up crop productivity, apiculture must be integrated with forestry.

WORLD AND ASIAN SCENARIO

About 5 crore honeybee colonies, mostly European honeybees, are maintained all over the world. They produce nearly 10 lakh Millions Tons honey and 1 lakh MT beeswax. Fifteen countries in the world account for 90 per cent of the world honey production. China leads with one crore bee colonies producing about 1.6 lakh millions tons honey, and 12,800 million tons beeswax. Beijing is the biggest exporter of honey, beeswax, and other honeybee products. America has 50 Lakhs bee colonies and Russia 50 Lakhs., Canada, Latin America, European countries, Australia, New Zealand are other important countries each maintaining 5 to 10 lakh bee colonies. Israel, a small arid country with geographic area equal to one or two Districts of India and with an average rainfall of only 7 to 8 inches, maintains 84,000 honeybee colonies, produces nearly 30 lakh Kg. of honey. Israel also uses these colonies for planned pollination of crops, making it 97 per cent self-reliant in crop production. While number of bee colonies in developed countries is decreasing due to insecticides and general pollution. China has increased the bee colony number from 60 lakhs to 1 crore during past five decades. India has about 10 lakhs indigenous bee colonies and 2 lakh imported European bee colonies. India is fortunate to have four species of honeybees and endowed with different types of forests and variety of agricultural and horticultural crops. By adopting a strategy to increase the number of honeybee colonies, India can also become a major producer and exporter of honey and beeswax.

Considering the area under forests and crops useful to honeybees, National Commission on Agriculture has estimated the potential of India at 5 crore Honeybee colonies. The Scientists at the Indian council of Agriculture have estimated that the country requires minimum 70 lakh honeybee colonies just to pollinate 12 important crops that depend on insects like honeybees for pollination. As against this minimum need, only 10 to 12 lakh bee colonies are available at present.

Beekeeping industry has quadruple benefits: 1) Producing lakhs of Kg. of honey and beeswax from the nectar of flowers which otherwise dries up and goes waste, 2) Providing employment to forest population, marginal farmers, and landless laborers, 3) Providing employment to rural educated youths in collection, processing and marketing bee-products and finally the most important, 4) Increasing productivity of various crops through bee-pollination.

According to the report of the National Family Health Services (2017), 50 per cent of the children under 5 years of age are undernourished. 50 per of the school going girls are anemic. The population of India is expected to reach at 150 crore by 2030.

Providing sufficient and nutritious food to all is the challenge before planners and agriculturists. Beekeeping Industry in its humble way can play an important role in increasing crop productivity and doubling the income of farmers. Making the farmers "Farmer-Beekeepers" and doubling the crop productivity is the need of the hour.

Keeping in mind the importance of honeybees, the KVIC has launched "Honey Mission" under which it will distribute 1 Lakh Bee boxes with bee colonies across the country to the farmers and prospective beekeepers. To celebrate the World Honey Bee Day on August 19, the KVIC set up an apiary of 200 bee boxes in Rashtrapati Bhawan. This will not only produce high quality honey and beeswax, but it will show that large government properties with lots of flora- fauna can be utilised for such novel purpose.

(The author is Chairman, Khadi & Village Industries Commission. Views are personal.)

KVIC revives historical training site at Pampore in J&K

NEW DELHI, Aug 22:

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) today revived its defunct training centre in Pampore district of Jammu and Kashmir which was destroyed decades ago during the peak of the militancy.

The occasion was marked by the installation of a statue of Mahatma Gandhi who in 1947 had visited the Pampore site, about 16 kms from Srinagar, and sat under a Chinaar tree to impart Charkha and loom training.

"We have revived the multi-disciplinary training centre in Pampore which was destroyed during peak of militancy in 1990s by installing solar charkhas and looms to spread Narendra Modi Government's message of peace," KVIC Chairman V K Saxena said.

He said the KVIC will spread the message of Prime Minister Narendra Modi, who on Independence Day resolved to reach out to the people of Jammu and Kashmir by embracing one another and not through "goli aur gaali" (guns and abuses).

The KVIC chief said Pampore has special significance as Mahatma Gandhi had on August 2, 1947, visited the place for three days and sat near a Chinaar tree there to give training of Charkha and loom making.

"The massive Chinaar tree is still there," he said, adding that the KVIC training centre was built at the same site.

Saxena said that within six months, the commission will complete the training of the programme and set up a Khadi India outlet at the same venue.

He said that in the ceremony today, which was also attended by Jammu and Kashmir Industries and Commerce Minister Chander Prakash Ganga, a solar charkha was installed for the first time in the State.

Saxena said the one month training programme on using the solar charkha for stitching and weaving would be linked with the Prime Minister's Gramin Awas Yojana.

"We have revived the training centre. 100 honey bee boxes have been established, charkhas set up and stitching and weaving work has begun. Poeple are very happy as after a long time there was a congregation of people," he said. (PTI)

प्रभात खबर

बंजारी में शुरू होगा खादी का उत्पादन, मिली मंजूरी

एलएलपी के संस्थापक को प्रमाणपत्र देते खादी के निदेशक.

संवाददाता ▸ गोपालगंज

अब अपने शहर में खादी का उत्पादन बढ़ेगा. देश में पहली एलएलपी (लिमिटेड लाइबलिटी पार्टनरशिप) को खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने मंजूरी दे दी है. खादी व ग्रामोद्योग के राज्य निदेशक एसके गुप्ता ने एलएलपी के संस्थापक नागेंद्र कुमार को प्रमाणपत्र देकर इसकी मंजूरी दी है. कुशग्राम खादी ग्रामोद्योग की वह संस्था बंजारी स्थित बबलू पेट्रोल पंप के पास खुली है. आयोग ने मंजूरी इस शर्त पर दी कि यहां तीन माह के अंदर खादी उत्पाद का कार्य लूम (कपड़ा बुननेवाला करघा) शुरू करना होगा. कुशग्राम खादी ग्रामोद्योग एलएलपी के संस्थापक नागेंद्र कुमार ने बताया कि खादी का उत्पाद कार्य शुरू होने से यहां के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि एलएलपी से जुड़ कर बेरोजगार युवा और महिलाएं फुल टाइम या पार्टटाइम अपना समय देकर कम लागत में एक बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं. महज सात से आठ हजार रुपये की लागत से देश की स्वतंत्रता की प्रतीक खादी उत्पाद को हमारी संस्था से खरीद कर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है.

NATION 5
THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in MUMBAI | SUNDAY | AUGUST 6, 2017

Govt to push khadi for military uniform

AFP

• FROM OUR BUREAU
New Delhi

After a move that has not yet fructified to make khadi as the dress code of all central government employees, the government is trying to push the swadeshi material for the military uniforms.

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) had approached the government to consider the khadi uniforms in the defence forces.

Those in the Army, however, say promotion of khadi is always welcome but the khadi uniforms will be difficult to maintain, particularly when the forces are deployed in hard outdoor conditions.

They say khadi material should undergo rigorous tests before introducing it for the military uniforms as it should be tested in terms of appearance, durability, comfort, ease of maintenance and costs.

The Army is already seeking help of the private industry to improve the design and quality of the uniforms to make them lightweight, breathable and skin friendly with anti-microbial properties. Khadi material will have to withstand all these tests before its introduction in the defence forces for the uniforms.

Those in the Army say promotion of khadi is always welcome but the khadi uniforms will be difficult to maintain, particularly when the forces are deployed in hard outdoor conditions

While the jawans and others in the rank and file have just two or three uniforms for wear, the Army officers wonder if khadi will meet the requirement of the variety of uniforms of different material worn by the officers that suit different climatic conditions.

The officers are supposed to wear different dresses for service and ceremonial occasions as there are different dresses for field duties, morning PT as also different mess dresses for summer and winter. They say khadi will not be suitable to meet all these requirements.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

WEDNESDAY 16 AUGUST 2017 — VARIETY

US envoy goes with public vote, chooses to wear a Kanjeevaram on I-Day

MaryKay went sari shopping in CP

MaryKay shared this picture of her in the Kanjeevaram yesterday

A few days back, MaryKay Carlson, Charge d'Affaires of the US Embassy, sought help from the Twitterati in choosing a sari to wear on Independence Day. She finally went with the 'voters' choice' and wore a maroon green Kanjeevaram. She shared a picture of her wearing the sari and wrote, "#SareeSearch success! Excited to attend #IndependenceDayIndia celebration wearing the voters' choice – Kanjeevaram. #WeWearCulture."

Earlier this month, Carlson had tweeted about her love for saris and ran an online poll to help her select a sari to wear on August 15. She regularly posted videos and pictures of her selected saris. Carlson went shopping at Khadi Bhawan in Connaught Place in the first week of August and surfed more than three dozen sarees to finally select five best ones. The five varieties selected by her were jamdani, dupion, Kanjeevaram and tussar.

Carlson's online sari campaign is another addition to the list of social media campaigns to promote Indian handloom. In the past, Smriti Irani's #CottonIsCool and #IWearHandloom have been a huge success.

— Divya.Kaushik@timesgroup.com

अमेरिकी राजदूत ने ट्विटर यूजर्स की चुनी साड़ी पहनी

एजेंसियां, नई दिल्ली : भारत में अमेरिकी दूतावास में कार्यवाहक राजदूत मैरिके कार्लसन ने 15 अगस्त को लोगों द्वारा चुनी गई साड़ी पहनी। कार्लसन ने ट्विटर पर चार अगस्त को चार साड़ियों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने भारत की जनता से पूछा था कि कौन सी साड़ी उन पर फब रही है। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के दिन कार्लसन ने लाल और हरे रंग की कांजीवरम साड़ी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, 'वोटरों द्वारा चुनी गई साड़ी को लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहनकर खुशी महसूस कर रही हूं।' तकरीबन 2000 ट्विटर यूजर्स ने कार्लसन को साड़ी चुनने में मदद की। सबसे ज्यादा वोट कांजीवरम साड़ी को मिले। साड़ी खरीदने के लिए कार्लसन राजधानी में खादी इंडिया के शो रूम पहुंचीं थीं। वहां उन्होंने चार साड़ियों- जामदानी, डुपियन, कांजीवरम और टसर को चुना था। इन चारों को पहनकर उन्होंने अपनी तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर शेयर की थी।

पोस्ट की फोटो सबसे अच्छी साड़ी चुनने के लिये वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने ट्विटर पर किया ओपिनियन पोल

आजादी की 70वीं सालगिरह पर मैरी पहनेंगी साड़ी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारत में अमेरिकी दूतावास की प्रभारी मैरी के कार्लसन भारत की आजादी की 70वीं सालगिरह को एक खूबसूरत साड़ी पहनकर सेलीब्रेट करना चाहती हैं। लेकिन, इस मौके पर वे कौन सी साड़ी पहनें इसके लिए उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक ओपीनियन पोल कराया है।

ट्विटर के जरिये वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक मैरी के कार्लसन अपने फॉलोअर्स से पूछ रही हैं कि 15 अगस्त के मौके पर कौन सी साड़ी पहनूं? उन्होंने इस बारे में एक वीडियो भी पोस्ट किया। ट्विटर पर हैशटैग साड़ी सर्च के जरिये कार्लसन फॉलोअर्स को साड़ी की फोटो पोस्ट करके उनकी राय जान रही हैं। हालांकि, कार्लसन अपनी इस कोशिश में कामयाब होती दिख रही हैं, क्योंकि इस पोल के जरिये खूबसूरत साड़ी की उनकी खोज अब केवल चार साड़ियों तक ही सिमट गई है।

साड़ियों का क्वार्टर फाइनल : कार्लसन ने अपने फॉलोअर्स की राय जानने के बाद ही अंतिम चार साड़ियों को सेलेक्ट किया।

अलग-अलग साड़ियों में मैरी के कार्लसन

उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद की गई इन चार साड़ियों को पहनकर अपनी पिक्चर पोस्ट की है। उन्होंने जामदानी, दूपियन सिल्क, कांजीवरम और टसर साड़ियों की कुल चार पिक पोस्ट की हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा- मेरी साड़ी की खोज जारी है। अपनी फेवरेट साड़ी को चुनकर आप मुझे ये बताने में मदद करें कि इंडिपेंडेंस डे पर मैं कौन सी साड़ी पहनूं।

साड़ियों से प्यार : कार्लसन दो बेटियों कैथरीन और केरन की मां कार्लसन ने विगत 2 अगस्त को दिल्ली के खादी इंडिया में साड़ी खरीदने का वीडियो भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा-मुझे इंडियन साड़ियों से प्यार है। मैं साड़ी की खोज में हूं ताकि इंडिपेंडेंस डे पर पहनने के लिए एक साड़ी चुन सकूं।

फॉलोअर्स ने की तारीफ : साड़ी सर्च शुरू करने के कुछ ही देर में फॉलोअर्स ने कार्लसन को अपनी राय भेजनी शुरू की। उन्होंने अच्छे इरादे के लिए कार्लसन की तारीफ भी की। एक यूजर ने लिखा- टसर मेरी पसंद है। हालांकि, ये बहुत नेक इरादा है। एक अन्य यूजर ने कहा- कांजीवरम।डुपियन भी बहुत अच्छी है। आप इन सबमें बहुत खुबसूरत लग रही हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

6 | mp nation

KVIC revives training site at Pampore in J&K

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) on Tuesday revived its defunct training centre in Pampore district of Jammu and Kashmir which was destroyed decades ago during the peak of the militancy.

The occasion was marked by the installation of a statue of Mahatma Gandhi who in 1947 had visited the Pampore site, about 16 kms from Srinagar, and sat under a Chinaar tree to impart Charkha and loom training. "We have revived the multi-disciplinary training centre in Pampore which was destroyed during peak of militancy in 1990s by installing solar charkhas and looms to spread Narendra Modi government's message of peace," KVIC Chairman V K Saxena said.

He said the KVIC will spread the message of Prime Minister Narendra Modi, who on Independence Day resolved to reach out to the people of Jammu and Kashmir by embracing one another and not through "goli aur gaali" (guns and abuses).

The KVIC chief said Pampore has special significance as Mahatma Gandhi had on August 2, 1947, visited the place for three days and sat near a Chinaar tree there to give training of Charkha and loom making. "The massive Chinaar tree is still there," he said, adding that the KVIC training centre was built at the same site. Saxena said that within six months, the commission will complete the training of the programme and set up a Khadi India outlet at the same venue.

He said that in the ceremony on Tuesday , which was also attended by Jammu and Kashmir Industries and Commerce Minister Chander Prakash Ganga, a solar charkha was installed for the first time in the state.

Saxena said the one month training programme on using the solar charkha for stitching and weaving would be linked with the Prime Minister's Gramin Awas Yojana.

"We have revived the training centre. 100 honey bee boxes have been established, charkhas set up and stitching and weaving work has begun. Poeple are very happy as after a long time there was a congregation of people," he said.

दैनिक जागरण

श्रीनगर में खादी प्लाजा व पांपोर में बनेगा ऊन बैंक

खादी ग्रामोद्योग

- केवीआइसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दी जानकारी
- लकड़ी के सबसे बड़े चरखे और प्रशिक्षण कक्ष का किया उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : ग्रीष्मकालीन राजधानी में जल्द ही विश्वस्तरीय खादी प्लाजा और पांपोर में ऊन बैंक बनेगा। यह जानकारी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (मंगलवार को पांपोर स्थित पीएमटीसी में (उत्पादन, विपणन एवं प्रशिक्षण) में एक बातचीत के दौरान दी।

पांपोर स्थित केवीआइसी का पीएमटीसी कश्मीर में आतंकवाद के शुरू होने के साथ ही लगभग निष्क्रिय हो गया था। इसे दोबारा बहाल करते हुए जीवंत बनाया जा रहा है। सक्सेना इसी सिलसिले में यहां आए हैं। उन्होंने पीएमटीसी, पांपोर परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में लकड़ी के सबसे बड़े चरखे और परंपरागत कश्मीरी तरीके से बने प्रशिक्षण कक्ष का भी उद्घाटन किया।

सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खादी मिशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ऐतिहासिक स्थान पर बना है। अगस्त 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दिन पांपोर में इसी जगह चिनार के नीचे बैठकर चरखा चलाया था। सक्सेना ने श्रीनगर में एक बड़ा खादी प्लाजा स्थापित करने का एलान करते हुए कहा कि इससे खादी और खादी उद्योग से जुडे स्थानीय लोगों को ही फायदा होगा।

दस्तकारी की वस्तुओं पर जीएसटी माफी पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संज्ञान में यह मामला लाया गया है। हम लोगों ने पहले ही केंद्र से खादी ग्रामोद्योग से जुडी दस्तकारी की वस्तुओं को जीएसटी मुक्त करने के संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी माफ करने का एलान करेगी। उन्होंने इस मौके पर कैनवास पेंटर नौशीन नजीर, चरखा कारीगर परवेज और सह निदेशक अनिल कुमार शर्मा समेत पीएमटीसी व उप कार्यालय केवीआइसी पांपोर के कर्मियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित भी किया।

'खादीची ७० दुकाने सुरू करू'

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

'भारत देश स्वतंत्र करण्यात महात्मा गांधी आणि त्यांच्या चरखाचे मोठे योगदान आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यला ७० वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या वर्षभरात खादी व ग्रामोद्योग आयोगातर्फे देशभरात खादीच्या दुकानांच्या ७० शाखा उघडण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांनी केली.

विमाननगर भागात देशातील पहिल्या 'इंडिया खादी' या दुकानाच्या शाखेचे उद्घाटन खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष विनयकुमार सक्सेना यांच्या हस्ते सोमवारी झाले.

खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडून सोमवारी पुण्यातील विमाननगर भागात देशातील पहिल्या 'इंडिया खादी' या दुकानाच्या शाखेचे उद्घाटन सक्सेना यांच्या हस्ते झाले. या वेळी खासदार अनिल शिरोळे, आमदार जगदीश मुळीक, विपणन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एस. राव, वाय. के. बारामतीकर, दुकानाचे चालक सौरभ चॅटर्जी आदी उपस्थित होते.

सक्सेना म्हणाले, 'महात्मा गांधीनी निर्माण केलेल्या खादीला आजच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओळख देण्याचे काम करीत आहे. पंतप्रधानांच्या पुढाकारामुळे देशभरात खादीच्या विक्रीत ३४ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून खादीचा प्रसार आणि प्रचार वेगाने वाढू लागला आहे. खादीचा उद्देश नफा कमविण्याऐवजी गावातील लोकांना रोजगार मिळवून देण्याचा आहे.'

शिरोळे म्हणाले, 'देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्ष पूर्ण होत आली. मात्र, शहराप्रमाणे गावाचा हवा तसा विकास झाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून गावाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खादीला प्रोत्साहन दिल्यास गावातील नागरिकांना रोजगार मिळेल.'

graduation, cadre, attentiveness towards signals, periodical rest & regular counseling of Loco Pilots were discussed and solutions were identified. Shri Ratan Lal, Chief Elec Eng, Shri P. S. Mishra, Chief Ops Mgr, WR along with other Sr Rly officers were present in this conference.

Khadi goes global, US Ambassador to wear Khadi Saree on Independence Day

In what comes as a matter of pride for the Khadi – the symbol of Swadeshi, used by Mahatma Gandhi during the Freedom Struggle – the US acting Ambassador to India Mary Kay Loss Carlson had visited the 'Khadi India' outlet at Connaught Place here on Wednesday as she has decided to wear a Khadi Saree during the Independence Day celebrations on Aug 15. Ms Carlson was received at the Khadi Bhawan by Ms Sangeeta Saxena, wife of KVIC Chairman V K Saxena, who guided the US envoy in choosing the Indian attires for her, besides describing the importance of Khadi. During her hour-long stay at the outlet, Ms Carlson got mystified with the big range of Khadi products there. She surfed more than three dozen sarees, to finally select five best ones for her, apart from some fine Khadi fabrics like raw silk, matka silk and katiya. She even tried few of them before the mirror that how it looked on her. Earlier, she also paid floral tribute to Mahatma Gandhi there. Meanwhile, enthused by the US Envoy's visit to 'Khadi India' outlet, KVIC Chairman V K Saxena said that it was an honour for Khadi artisans. "What else can be a better pride for us that the Ambassador of the first democracy of the world has visited our outlet, to select the sarees for the occasion of the 70th anniversary of our democracy," he said.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

कपड़ों पर जीएसटी हटाने के आसार

5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल में हो सकता है फैसला

■ नवभारत रिपोर्टर । रायपुर

कपड़ों पर टैक्स हटने के आसार बढ़ गए हैं. कपड़ा बाजार से जुड़े कुछ दिग्गजों ने इस संवाददाता को बताया कि 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली में हो रही है जिसमें कपड़ों पर टैक्स हटाए जाने की पूरी संभावना है. कपड़ा कारोबारियों ने टैक्स नहीं हटाए जाने पर फिर से हड़ताल की धमकी दी है. कपड़ा क्षेत्र के दिग्गजों का कहना है कि यदि कपड़ा पर जीएसटी खत्म नहीं किया गया तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में स्थित कपड़ा उत्पादनकर्ता और व्यापारी फिर से हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुके हैं.

जीएसटी काउंसिल ने कपड़ो पर टैक्स लगा दिया है. एक हजार से कम के कपड़ों पर 5 फीसदी और उससे ज्यादा पर 12 फीसदी जीएसटी है. निर्माता और व्यापारी इसी का विरोध कर रहे हैं. गुजरात, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र में कपड़ा निर्माताओं ने इसका कड़ा विरोध करते हुए पखवाड़ेभर तक आंदोलन किया था. इसके बाद केंद्र सरकार के उच्च स्तर पर पहल के बाद यह हड़ताल स्थगित कर दी गई. लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो कपड़ा सेक्टर सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा. साथ ही सरकार को भी बड़े राजस्व से हाथ धोना पड़ सकता है.

छत्तीसगढ़ भी हुआ प्रभावित

कपड़ा निर्माताओं व कारोबारियों की हड़ताल से छत्तीसगढ़ के कपड़ा कारोबार पर भी अच्छा खासा असर पड़ा. हालांकि मुम्बई व कोलकाता के बीच स्थित सबसे बड़ी कपड़ा मंडी पंडरी रायपुर के पूर्व अध्यक्ष सुशील अग्रवाल का कहना है कि जुलाई में वैसे भी आमतौर पर हर साल कारोबार ठंडा रहता है, जीएसटी का असर भी पड़ा है.

हो रहा सिर्फ 50 फीसदी कारोबार

उन्होंने बताया कि राज्य में जुलाई में रोजाना ढाई से तीन करोड़ रुपए के कपड़ों का कारोबार होता है, लेकिन इस बार जीएसटी की वजह से यह धंधा आधा ह[...] चार सौ से ज्यादा होलसेलर [...] रिटेलर हैं. इन रिटेलरों में से [...] कम्पोजिशन के दायरे से भी [...] सिर्फ दस फीसदी बड़े व्यापारि[...]

दैनिक जागरण

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

जल्द जीएसटी से मुक्त किया जाएगा कपड़ा कारोबार को...!

झुकेगी सरकार, मिलेगी व्यापारियों को राहत

हिरदाराम नगर प्रतिनिधि

अगर सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो कपड़ा कारोबार जीएसटी से जल्द मुक्त होगा। इसके दो मुख्य कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तो सूरत एवं अहमदाबारद में चल रही कपड़ा व्यापारियों की लम्बी हड़ताल दूसरे इसी साल गुजरात में होने वाले विधान सभा चुनाव। इधर, उत्तर प्रदेश में कपड़ा व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आश्वासन पर जिस तरह से हड़ताल समाप्त की, उससे भी जीएसटी को कपड़े से मुक्त रखने के संकेत मिले हैं। सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है और वहां से भी संकेत मिले हैं कि कपड़े को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है।

विधान सभा चुनाव पर पड़ सकता है असर : सूत्रों के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार को जो खुफिया सूचनाएं मिली हैं, उनमें कहा गया है कि गुजरात सहित समूचे देश का कपड़ा व्यापारी जीएसटी से काफी आहत है। सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदा, मुम्बई, कलकत्ता सहित कपड़े के बड़े-बड़े उत्पादक शहरों के व्यापारी जीएसटी से परेशान हैं।

भाजपा का वोट बैंक हैं व्यापारी : गुजरात व मध्यप्रदेश सहित देश का अधिकांश व्यापारी वर्ग भाजपा समर्थक है। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां व्यापारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जीएसटी को लेकर भाजपा समर्थक व्यापारी अपनी ही पार्टी से बेहद खफा है। सूरत और अहमदाबद में कपड़े का उत्पादन नहीं हो रहा है। देश में साठ फीसदी कपड़ा इन्हीं दो शहरों से सप्लाई होता है।

जीएसटी के कारण भाजपा समर्थक व्यापारी इस पार्टी से दूर होता जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार कपड़े पर टैक्स लगा है जिसके बाद कारोबार करना मुश्किल हो गया है।

• वासुदेव वाधवानी,
अध्यक्ष कपड़ा एसोसिएशन

Khadi may get GST exemption, says minister

New Delhi: Minister for micro, small and medium enterprises (MSME) Kalraj Mishra on Friday said that he was hoping that Khadi products would be exempted from Goods and Service Tax (GST) in the coming days. Currently, khadi products face a 5% levy while the tax on goods produced by village industries is 12%.

While addressing the meeting of Khadi Institutions of the country here at India Habitat Centre on Friday, Mishra said that for the larger interest of weavers and spinners associated to khadi industries, the GST panel had started analysing the pros and cons of GST exemption, to benefit the workers, weavers and spinners — associated with Khadi.

"Even the finance minister (Arun Jaitley) had assured me to give a GST exemption for the financial development of [...]nomically ba[...] weavers and [...] said. TNN

अब खादी की दीवानी हुई अमेरिकी दूतावास, 15 अगस्त के लिए खरीदी खादी की साड़ी

डिजिटल डेस्क | नई दिल्ली

हम भले ही खादी को उतना महत्व न दें, लेकिन विदेशियों के लिए खादी बहुत महत्व रखता है और जबसे केंद्र में मोदी सरकार आई है, वो खादी के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं कर रही है। अब अमेरिकी दूतावास में सीनियर ऑफिसर मैरिके कार्लसन को खादी की दीवानगी चढ़ गई है। इसके लिए वो गुरुवार को दिल्ली के कनाट पैलेस में खादी आउटलेट में गई और 5 खादी की साड़ियां खरीद कर ले आईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैरिके कार्लसन ने 15 अगस्त के दिन 70वें इंडिपेंडेंस डे पर खादी की साड़ी पहनने का मन बना लिया है। जब वो साड़ी खरीदने के लिए आउटलेट पर गईं, तो वहां जाते ही वो कंफ्यूज हो गईं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि, 'यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं और इनमें से सिलेक्ट करना बहुत टफ है। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है।' इसके बाद कई लोगों ने उन्हें ट्विटर पर सजेशन दे डाले। कई लोगों ने तो उन्हें बनारसी साड़ी ट्राय करने को भी कहा।

केवीआईसी का क्या है कहना? खादी विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन (केवीआईसी) ने बताया कि कार्लसन ने यहां से 5 साड़ियां खरीदी है। इससे पहले उन्होंने कई साड़ियों को ट्राय किया, लेकिन उनमें से 5 बेस्ट साड़ियों को उन्होंने खरीदा। इनमें से एक वो इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में पहनकर जाएंगी।

ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखें-
http://www.bhaskarhindi.com

गांधी की खादी भी जीएसटी के दायरे में, खादी संस्थाओं में रोष

अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत।

गांधी की शादी पर भी जीएसटी लग गया है। ऐसे में खादी का काम करने वाली संस्थाओं के सामने समस्या आन खड़ी है। इसके साथ ही संस्थाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी के चलते 14 जुलाई तक खादी केंद्रों पर बिक्री बंद करने का फ़ैसला लिया।

खादी संस्थाओं की एक बैठक शनिवार को खादी आश्रम स्थित सोमभाई हाल में संपन्न हुई। जिसमें प्रदेश की खादी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा की अध्यक्षता खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर सैनी ने की, जबकि संचालन संस्था संघ के सचिव आनंद कुमार शरण ने किया।

इस अवसर पर सतपाल सैनी, मुनीष रानी, वीरभान सिंह, प्रवीन सैनी, मुकेश कुमार शर्मा, ब्रह्म सिंह व संजय गोदारा मौजूद रहे।

पारित प्रस्ताव

- खादी को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाएं।
- कत्तिनों व कामगारों की मजदूरी का नगद भुगतान ही किया जाएगा।
- प्रदेश की खादी संस्थाएं अप्रैल-2017 से खादी ग्रामोद्योग आयोग से कोई भी एमएमडीए क्लेम नहीं करेंगी। एमएमडीए के अनुसार संस्थाएं थोक बिक्री पर पांच प्रतिशत छूट देंगी।
- खादी संस्थाओं द्वारा ऋण लिया गया है, उसके समक्ष खादी संस्थाओं द्वारा अपनी संपत्तियां मोर्टगेज करवाई गई है, जिनकी कीमत के लिए गए ऋण से कई गुणा अधिक है। इसलिए आयोग खादी संस्थाओं के ऋण के समक्ष के कागजात रखकर बाकी संपत्तियों के कागजात खादी संस्थाओं वापस करें और संस्थाओं को अपने कार्य को बढ़ाने के लिए अपनी सरप्लस संपत्ति को बिक्री करने का अधिकार हो।

बिहार : 'हफ्ते में दो बार खादी पहनें अधिकारी'

■ **एजेंसियां, पटना :** बिहार में राज्य के खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने आईएएस अधिकारियों समेत सभी सरकारी कर्मचारियों से हफ्ते में कम से कम दो बार खादी पहनने की अपील की है। बिहार में इस साल चंपारण सत्याग्रह शताब्दी महोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। खादी बोर्ड के सीईओ बी.एन प्रसाद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के खादी को बढ़ावा देने के अभियान के तहत हमने यह अपील की है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

चरखा चलाने के लिए नहीं आ रही हैं पूणी

खादी पर जीएसटी से बुनकरों की हालत हुई खस्ता

रोजी-रोटी का गम्भीर संकट बना

ब्यूरो/ नवज्योति जयपुर

खादी के इतिहास में पहली बार खादी पर लगी जीएसटी से खादी के कतिन-बुनकरों की हालात खस्ता हो गई है। खादी का सूत कातने वाली कतिन-बुनकरों के पास कातने के लिए सूत नहीं मिलने से उनकी रोजी-रोजी का संकट पैदा हो गया है। खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं ने एक जुलाई से लगी जीएसटी की मार के चलते काम कम किया है, जिसका सीधा असर अलसुबह से ही सूत कातकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली महिलाओं पर पड़ा है। केन्द्र की मोदी सरकार ने खादी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाकर खादी को ओर महंगा कर दिया है। बस्सी कस्बे में सूत कातकर अपना पेट भरने वाली कांता महावर ने बताया कि जुलाई माह में पुणी नहीं आने से सूत काता नहीं गया, जिससे आने वाले दिनों में घर चलाने में परेशानी आएगी। इसी तरह गीता देवी का कहना है कि अब तो बिल्कुल ही माल नहीं आ रहा है, संस्था वाले भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। पिछले कुछ समय से अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अब तो पूरी मंदी से आ गई है।

बुनकर हुए बेरोजगार-
खादी के बुनकर भी बेरोजगारी की भेट चढ़ने लगे हैं। बांसखोह गांव के राकेश ने बताया कि दरी, छोटी दरी सहित अन्य छोटे-मोटे कार्य वर्षभर चलते रहते थे, लेकिन अब तो हालात खराब हो गए हैं। खादी संस्था से जुड़े दामोदर महावर ने बताया कि यदि खादी पर जीएसटी नहीं हटाई जाएगी तो खादी का काम करने वाले बुनकर, खादी कतिन की हालत खराब हो जाएगी। उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं होने से उनके सामने बड़ा संकट है।

तिरंगे का कपड़ा भी दौसा में बनता है-
प्रदेश में दौसा, बस्सी खादी का कपड़ा देश भर में प्रसिद्ध है। तिरंगे के काम में आने वाला खादी का कपड़ा भी दौसा में तैयार होता है। हालांकि, खादी की गांधी टोपी, नेशनल फ्लैग, सूती धागों को जीएसटी से मुक्त रखा गया है।

संस्था संघ ने भी लिखा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र-
राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ ने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर खादी से जीएसटी हटाने की मांग की है। संस्था संघ के मंत्री जवाहरलाल सेठिया ने भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि खादी पर अतीत में कभी भी जीएसटी नहीं लगा है, ऐसे में खादी को जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए।

इनका कहना है

बापू की खादी पर जीएसटी लगाकर केन्द्र सरकार बापू का अपमान कर रही है। ब्रितानी हुकूमत में अंग्रेजों ने भी खादी पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया, लेकिन अब भाजपा सरकार आजादी से जुड़ी सभी यादों को खत्म करना चाहती है। हमारे बस्सी क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग खादी से जुड़े थे, जो अब पूरी तरह बेरोजगार होने के कगार पर पहुंच गए हैं।

-कविता मीना, प्रदेश सचिव, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान एवं पूर्व सरपंच झर

बिहार

आज का दिन 1850 में अमेरिका के डॉ. जॉन गोरी ने कृत्रिम तौर पर (मशी... जमाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया।

आजादी के बाद पहली बार खादी पर लगा टैक्स

06 ... **400** ...

बाहर से आता है कच्चा माल

ISSN-0971-7153

মৌমাছি দিবস উপলক্ষে সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা। — শনিবার সকালে প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে তোলা সংবাদচিত্র।

মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

সিপাহিজলা জেলায়

নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল প্রশাসন

Central Board of Excise and Customs

Goods and Services Tax

22. Persons liable for registration.

(1) Every supplier shall be liable to be registered under this Act in the State or Union territory, other than special category States, from where he makes a taxable supply of goods or services or both, if his aggregate turnover in a financial year exceeds twenty lakh rupees:

Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category States, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakh rupees.

(2) Every person who, on the day immediately preceding the appointed

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ

जागतिक मधमाशीपालन दिनानिमित्त डहाणूत जनजागृती कार्यक्रम!

शिरीष कोकीळ ●

डहाणू दि. २० : जागतिक मधमाशीपालन दिनाचे औचित्य साधून खादी ग्रामोद्योग केंद्र येथे भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मधमाशांचे पर्यावरणातील महत्वाचे स्थान, मधमाशी पालनाच्या पद्धती, ती चावल्यास करावयाच्या उपचारपद्धती याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

यावेळी डहाणू येथील खादी ग्रामोद्योग केंद्राचे प्राचार्य विलास लाडे, विकास अधिकारी सुरेश गायकवाड, तांत्रिक विभागाचे प्रमुख वाय. आर. टिपल, तांत्रिक अधिकारी (मध) संजय पाटील, कृषी अधिकारी संजय शेंडे, डहाणूच्या उप जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ए. डी. यादव यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

सकाळच्या सत्रामध्ये शाळेचे विद्यार्थी, तालुक्यातील अती दुर्गम भागातील अल्प भूधारक शेतकरी, बेरोजगार युवक यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. या सत्रात वैद्य प्रीती पतिलोंनी कुंकडे यांनी वैद्यकीय दृष्ट्या मधाचे महत्व विशद केले. मधमाशा पालनानंतर त्यावरील उपायांची सविस्तर माहिती सर्व उपस्थितांना देण्यात आली. संजय पाटील यांनी मधमाशा पालनासाठी वापरण्यात येणारी पेटी, मधमाशा हाताळण्याची पद्धत, त्यातील बारकावे, नैसर्गिक आपत्तीपासून या मधमाशांच्या पेटीचा कसा बचाव करायचा याबाबत प्रात्यक्षिकासह सविस्तर माहिती दिली व उपस्थितांच्या शंकांचे समाधानकारक निरसन केले.

दुपारच्या सत्रामध्ये शासकीय विभागातील अधिकारी, मधमाशा पालन करत असलेले बागायतदार, नवीन व्यवसाय सुरु करू इच्छिणारे शेतकरी, जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मधमाशा पालन उद्योगात येणाऱ्या अडचणी, त्यावर करावयाची उपाय योजना याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

वाय. आर टिपल यांनी प्रास्ताविक केले. तर विलास लाडे यांनी स्वतः तयार केलेल्या चित्रफितीद्वारे सादरीकरण केले. सुरेश गायकवाड यांनी मधमाशी पालनाच्या व्यवसायासाठी वित्तीय साहाय्य याबाबतच्या उपलब्धींची माहिती दिली. संजय पाटील यांनी मधमाशी पालन करताना आलेले अनुभव, तिथे येणाऱ्या अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीच्या उत्पनात झालेली घट, निसर्गाचा असमतोल याबरील उपायांना सहाय्यभूत ठरेल असा मधमाशा पालनाचा जोडधंदा करावा, असे आवाहन केले. आयुर्वेदिक उपचारांमुळे मधाला आपल्या आयुष्यात अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मधाला चांगली बाजारपेठ देखील उपलब्ध आहे. यामुळे मधमाशा पालनाच्या व्यवसायाला उज्वल भविष्य असून ठाणे आणी पालघर जिल्ह्यातील शेती बागायती, जंगलाखाली येणारे क्षेत्र, पोषक वातावरण याचा विचार करता मधमाशा पालनासाठी आपला परिसर फारच उपयुक्त आहे. त्यामुळे जास्तीजास्त लोकांनी सरकारी योजनांचा फायदा घेऊन या व्यवसायाकडे वळावे, असे कळकळीचे आवाहन देखील पाटील यांनी केले. विनायक बारी यांनी देखील मधमाशी पालनाबाबतचा अनुभव सांगून

मधु किट का उद्घाटन

अहमदाबाद. विश्व मधुमक्खी दिवस के उपलक्ष्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्थानीय कार्यालय की ओर से निदेशक संजय हेडाऊ व टीम ने मधु किट का उद्घाटन करवाया।

उन्होंने मधुमक्खी एवं मधु के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा, महिला व बाल कल्याण राज्यमंत्री डॉ. निर्मला वाधवानी से मुलाकात करके मधुमक्खी की जानकारी देते हुए मधु किट का उद्घाटन करवाया।

यहां गांधी आश्रम स्थित विनय मंदिर की छात्राओं को मधुमक्खी व शहद की जानकारी दी गई और शहद के नमूने छात्राओं व स्टॉफकर्मियों को वितरित किए। आयोग की टीम में डी.सी. सिंघल, जगबीरसिंह, अश्विन बारोट आदि शामिल थे।

Times Special THE TIMES OF INDIA, MUMBAI MONDAY, FEBRUARY 27, 2017

BEES SHOW BRAIN POWER OF INSECTS

Intelligent insects? You wouldn't think so until you considered the humble bumblebee. In the latest triumph for one of humanity's favorite insects, bumblebees learned how to push a ball to the centre of a platform for an experiment. Now, it may be premature to train them to play chess, but scientists say the bees show that just because a brain is small doesn't mean it is simple

A GIANT STEP

- In the experiment, reported in the journal Science, researchers trained bees to push a little ball to the centre of a platform
- The task was completely arbitrary for the bees as they don't do anything like this in nature, where they seek out flowers for nectar and pollen
- So, it was a brand new behaviour demanding some kind of general ability to learn

SMART LEARNERS

- The bees learned best by watching a fellow bee perform the feat. That kind of imitation is social learning, say the researchers, more often seen in animals with much bigger brains, like monkeys
- Honeybees use a tail-shaking behaviour called the waggle dance to tell each other where to fly for flowers with nectar, and to signal how good the nectar is
- That's like twerking the address of the supermarket and also giving a review of its produce section

Bees have nearly a million brain cells, compared with about **250,000** brain cells in the fruit fly

SO, CAN INSECTS THINK?

Clint Perry, a bumblebee trainer at Queen Mary University of London, says a number of recent experiments have shown that "insects can solve problems, they can learn"

Evidence shows that even fruit flies remember and choose between alternative actions

But scientists have yet to define the limits of the mental abilities of insects, once thought to be little automatons, hard-wired to take certain specific actions

Source: NYT

Thousands of people on online forums have faced it in some form or the other, but trolling ... continues to grow unchecked. But ... to counter

मधु क्रांति की दिशा में कदम

मुंबई, कासं. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के मधु क्रांति के सपने को साकार करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मुंबई में विश्व मधु दिवस मनाया.

इस अवसर पर केवीआईसी ने विद्यालय विकास मंडल के श्रमिक विद्यालय के 100 से अधिक छात्रों को 50 ग्राम शहद की बोतलें बांटी . केवीआईसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाई.के.बारामतीकर ने कहा कि स्वीट क्रांति का मुख्य कारण न केवल बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है बल्कि उन्हें मधुमक्खी पालन के तरीके भी सिखाना है. ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके. बारामतीकर के अनुसार मधुमक्खी पालन का तरीका जान किसान आसानी से अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं.